ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS OF HIMACHAL PRADESH AGRO-INDUSTRIES CORPORATION, LTD., SIMLA

SHRI PRABHUDAS PATEL: I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himachal Pradesh Agro-Industries Corporation Limited, Simla, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-9901/75.]

11.12 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance (Amendment) Bill, 1975, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th July, 1975, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 29th July, 1975, agreed without any amendment to the Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill, 1975, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th July 1975."

11.14 hrs.

STATEMENT *RE.* SITTINGS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, I would like to announce that the sittings of the House will stand extended till Monday. As it is, it is scheduled to conclude on the 31st July, 1975. Thus, there will be a sitting on Friday, the 1st August and also on Monday, the 4th August.

11.15 hrs.

BANKING SERVICE COMMISSION BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: We now take up further consideration of the Banking Service Commission Bill. Shri Darbara Singh was on his legs. He may continue his speech.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : स्पीकर साहब, मैं कल अर्ज कर रहा था कि 22 बैंकों में अब तक जो स्टाफ है उस की स्कूटिनी होनी चाहिये । क्योंकि बैंकिंग कमीशन ने रिपोर्ट की है कि नान-मैट्रिकुलेट्स और ऐसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं थे उन को भर्त्ती कर लिया गया । किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, किसी न किसी ढंग से उन को रख लिया गया । जाहिर है कि ऐसे लोगों की ऐफिशियेंसी अच्छी नहीं हो सकती । पिछली जो रिपोर्टस ले की गई हैं उन में बताया गया है कि इन बैंकों में 88 लाख रु० का लैस प्रौफिट हुआ है । इस की बजह यह है कि एफीशियेंसी नहीं रही है और ऐसे लोग भर्त्ती किये गये जो क्वालिफाइड नहीं थे । फैसला किया गया है कि नये ग्रैजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स और टेक्नीकल आदमी लिये, जायेंगे । बड़ी अच्छी बात है । लाखों की भर्त्ती होती है इन बैंकों में । कई बैंक वक्त पर पता नहीं देते । अब आप ने कहा है कि 25

परसेंट हो तो बता दें, रेगुलर बताते रहे । लेकिन भर्ती अब उन के जिम्मे नहीं रही है, बल्कि कमीशन करेगा । लेकिन मै अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे जो बैंक हैं क्या उन के बारे में आपने कभी सोचा कि उन की भर्त्ती कैसे हो रही है । अपनी मर्जी के आदमी रखते है, जो क्वालिफिकेशन्स आप ने रखी है उन से कम क्वालिफिकेशन के लोग भर्त्ती कर रहे हैं । कल को अगर उन को नेशनेलाइज करना होगा तो ऐसा इन-एफिशियेंट स्टाफ मिलेगा कि जिस का कोई हिसाब नही है । इसलिये आप क्यों नहीं उस को अपने परव्यू में लेते ताकि सभी बैंकों की भर्त्ती बैंकिंग कमीशन के जरिये हो जिस से उन की निस्वती बराबर हो ।

आप ने कहा है कि 15 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स और साढे 7 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जगह दी जायेगी । मुझे पता नहीं यह कहा तक पूरा होगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो आप ने रखा है, जो कमीशन की रिपोर्ट है उस मे कहा गया है कि कोशिश करनी चाहिये कि मैनेजर ऐसा हो जो लोकली अच्छा हो और सब को जानता हो ताकि लोगों से पैसा अट्रेक्ट कर सके । जो आप शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को रखना चाहते हैं उन को आप अकोमोडेट करेंगे कि नही, क्योंकि अभी यह होता है कि उन की खाली जगहें खाली नही रखी जाती हैं, बल्कि उन को भर लिया जाता है यह कह कर कि सूटेबिल आदमी नहीं मिले । अब ऐसी कोई बात न हो और यह बहाना कायम न रहे इस पर आप को ध्यान देना चाहिये ।

एक रिकमन्डेशन यह भी है कि ऐग्रीकल्चर रीफाइनेंस कमीशन और ऐग्रीकल्चर फंड्स कमीशन को मिला कर एक करना चाहिये ताकि कोई कनफ्यूजन न रहे । जो रिपोर्ट लोक सभा में दी गई उस मे कहा गया कि 51.2 परसेंट नई शाखाये खोली हैं 1969 से ले कर अब तक दुगनी ब्रांचेज खोली गई हैं । बड़ी अच्छी बात है और इस का ऐक्सटेंशन 55.2 परसेंट देहात में हुआ है । लेकिन एक सिफारिश की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह कि प्राइमरी क्रैडिट सोसाइटीज के जिम्मे बहुत काम डाला है और साथ यह भी कहा है कि ऐग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसाइटीज को और तरजीह देनी चाहिये जिस से वह कर्जा दे पाये और उन का ताल्लुक कर्माशियल बैंक्स से हो । आज का जो कोआपरेटिव सिस्टम है उस मे रिवोल्यूशनाइज तरीके से काम करने की जरूरत हैं क्यो कि आज की जो सोसाइटीज हैं उन की खराबियां आप के सामने हैं । आप रिपोर्ट को अगर देखें तो ऐसा मालूम होगा कि इस का जो ढांचा है, वह पहले से गिरा हुआ है और जो डिफाल्टर्स है और जो वाइंड अप सोसाइटीज है, जिन का कर्जा रह गया है, उस को आप को राइट आफ करना पड़ता है । इसलिए मेरा कहना यह है कि आप कोआपरेटिव्ज को नये ढंग से ढाले और जो प्राइमरी सोसाइटीज है जिन के जिम्मे आपने कर्जा देना लगाया है, उनको मजबूत करे । यह भी उन्होने कहा है कि जो कर्माशियल बैंक्स है वे कर्जा दे ताकि वे आगे कर्जा दे पाए । आप ऐसे बैंक्स बनाए जो उन को कर्जा दें । इस के लिए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो आफिसर्स कमीशन ने भर्त्ती करने है, उन को अच्छे ढंग से चुने । मैं यह कहूंगा कि स्टेट्स मे रीजन्स मुकर्रर करने चाहिये और वहां पर आप को अच्छे बढ़िया आदमी रखने चाहिए जिस से वे देहातों से डिपोजिट्स को कलेक्ट कर सकें । इस ढंग से आप नही करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है और आप के डिपोजिट्स शार्टेन होते जाएगे नीचे होते जाएगे । इस के बारे में जो एड वाइस देने वाले है कमीशन को, उस में इस का भी इन्द्राज करे ।

एक चीज मैं यह भी अर्ज करना चाहता हू कि फारेन करंसी के बारे में कुछ पहले से ज्यादा इन्क्रीमेंट हुआ है । जो लोग बाहर दूसरे मुल्कों में हैं और अपना रुपया पैसा यहां

[श्री दरबारा सिंह]

भेजते हैं, उन को सहूलियतें मिलनी चाहिए। वे छोटी इंडस्ट्री और दूसरी चीजों के लिए रुपया भेजते हैं।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि देहातों के लिए यह कहा गया है कि वहां पर लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए लेकिन वह ज्यादा इन्ट्रेस्ट पर देना चाहिए। क्यों, इसलिए कि वहां पर खर्च का मार्जिन ज्यादा आता है। उन का कहना है कि शहरों में कम इन्ट्रेस्ट पर और देहातो मे ज्यादा इन्ट्रेस्ट पर कर्जा देना चाहिए। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह जो रिपोर्ट में कहा गया है कि देहातवालों से इन्ट्रेस्ट ओवर एंड एबाव ज्यादा चार्ज करना चाहिए, जोकि आज किया जाता है उस से ज्यादा चार्ज किया जाए, यह बात मैं समझता हूं ठीक नहीं है। वे दबे हुए हैं और आप उन की इनडेटेडनेस को रिमूव करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि उस को माफ कर दिया जाए और दूसरी तरफ आप नये इन्ट्रेस्ट की मारफत उन लोगों पर बोझ डालना चाहते हैं।

इस के बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सेल बना हुआ हैं, इस सेल ने दो तीन बातें की हैं कि जो यहां मोटर साइकिल लेने वाले हैं या जो ऐसी छोटी-मोटी चीजों के लिए कर्ज लेने वाले हैं उन को प्रायरटी दी जाए। मैं चाहूंगा कि छोटी इंडस्ट्रीज देहातों में लगाने के लिए और छोटे छोटे यूनिट्स वहां पर स्थापित करने के लिए भी उस को एडवाइस मिलनी चाहिए। रिकमेंडेशन में यह है कि मैनेजमेंट सोसाइटी ऐसी बनाए जो एडवाइस देने वाली हों। वे भी आप को बनानी होंगी। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पंजाब के लोग दुनिया भर में अपनी मेहनत और मजदूरी कर के पैसा कमाते हैं और उस में से बहुत सा रुपया इसलिए उन के पास रुका पड़ा हुआ है क्योंकि उस को इस्तेमाल करने के लिए ठीक ढंग से कोई एडवाइस नहीं मिल रही है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया वहां से आ सकता है। जैसे नजदीक के चार, पांच देहातों में चार चार बैंक खुले हुए हैं जोकि नेशनेलाइज्ड बैंक हैं। इस के अलावा और भी बैंक हैं और उन बैंकों में करोड़ों रुपये का सरमाया है, लेकिन वह जाता कहां है। वह सरमाया बम्बई और कलकत्ता जाता है और जो मीडियम और स्माल फार्मर्स हैं, जो मीडियम कर्जा या छोटा मोटा कर्जा लेने वाले स्माल फार्मर्स हैं, उन को उन बैंकों से कर्जा कम दिया जाता है। वह सरमाया इंडस्ट्री और कमर्शियल तौर पर लगता हैं और प्रोफिटएबिल इंस्टीट्यूशन्स में ज्यादा लगाया जाता है ताकि ज्यादा प्रोफिट मिल सके। इस का मतलब यह नहीं है कि आप उन छोटे लोगों के लिए इन्तजाम न करें। आज जो स्माल फार्मर्स हैं, जो कि प्रोडक्शन करते है, उन के लिए पैसे की कोई भी सहूलियत न मिले, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उन को पैसा मिलना चाहिए। आज जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं या एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं, जो कि किसानों को कर्जा देती हैं, उन को पैसा दिया जाए। आज जो स्माल फार्मर्स हैं उन को शार्ट टर्म लोन की अजहद जरूरत है और उन को कर्जा मिलना चाहिए।

एक यह भी रिकमेंडेशन की गई है कि जहां दो फसलें खराब हो जाएं और वहां पर किसान डिफाल्टर हो, तो उस की रिकवरी फ्लेक्सिबिल होनी चाहिए। अगर बारिश लगातार नहीं होती है और दूसरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वहां पर कर्जा रिजिडली नहीं वसूल करना चाहिए बल्कि वह पेनेसिविल होना चाहिए।

एक बात यह अर्ज कहना चाहता हूं कि यह ओवरटाइम की बीमारी बैंकों में बहुत है। ऐसा कौनसा काम है, जिस को उन्हें दफ्तर के टाइम के बाद करना है। आप अन्दाजा लगाइए कि कितना ओवरटाइम सारे दफ्तरों में दिया जाता है। जब बजट तैयार किया जाता

है जो जो नीचे के सुपरिन्टेंडेंट होते हैं दफ्तरों में वे उस वक्त उस को तैयार करना शुरु करते हैं जब बिल्कुल नजदीक बजट का समय आजाता है और पांच, पंच और सात सात घंटे ओवरटाइम के लगा लेते हैं। इस तरह से हर जगह यह बीमारी है और यह बडी क्रोनिक हो गई है। हर महकमे मे यह चली गई है। इस इंस्टीट्यूशन मे जहां आप लाखो लोग भर्ती करते हैं वहां पर अगर कोई 10 बजे से 5 बजे तक आफिस टाइम में अपना काम पूरा न करे, तो उस की एकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि वह काम करता है या नही और अगर नही करता है तो उस को सजा मिलनी चाहिए। होता क्या है कि पाच बजे तक तो काम होता नही है और उस के बाद काम कर के चार, चार पांच पाच घटे ओवरटाइम के बना लिये जाते है। यह सब बद होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आज एक चपरासी की तनखाह जो है वह बडे बडे अफसरों से ज्यादा हो गई है क्योंकि वह ओवरटाइम कमाता है। यह ओवरटाइम की बीमारी आप बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के टेंटेकल्स इतने फैल गये हैं, इतने बडे भारी बोझल हो गये हैं और स्टाफ इतना ज्यादा हो गया है कि इस मे कमी करने की जरूरत है। बजाए कम करने के आप उन को ओवर-टाइम देते है। मेरा कहना यह है कि आप इस ओवरटाइम को यक-कलम खत्म कर दीजिए ताकि लोगों को सहूलियतें हम दे सकें और उन को राहत मिल सके।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हू, छोटे लोगों को जैसे कि कारपेन्टर्स है, आर्टीशन्स हैं, उन को कर्जे की सहूलियतें मिलनी चाहिए और आपने भी कहा है कि वे सहूलियतें उन को मिलेंगी और एक बैंक ने—सेंट्रल बैंक आफ इंडिया—यह बात शुरू की है और उन्होंने कहा है कि हम इस सहूलियत को और बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

स्लम्स क्लियरेंस स्कीम्स में होना, बहुत अच्छी बात है। स्लम क्लियरेंस टी०वी पर भी दिखलाया जाता है लेकिन मैं यह देखता हूं कि स्लम क्लियरेंस एक तरफ खत्म होता है तो दूसरी तरफ वह शुरु हो जाता है। दिल्ली मे ऐसा वातावरण बना है कि एक जगह से स्लम्स खत्म किये जाते हैं तो दूसरी तरफ नये स्लम्स कायम हो जाते हैं। जिन को एलाटमेंट होता है तो वह एलाटमेंट दूसरे लोगों को बेच देते है और बड़े आदमी उन को ले लेते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस पर बंदिश होनी चाहिए कि जिस आदमी के नाम पर एलाटमेंट होता है, वह दूसरे को नहीं बेच सकता। इस प्राब्लम को भी आप को देखना चाहिए।

अब मै बैंकों में कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर लोग नान-मैट्रिक है और उन के ही रिश्तेदार वहां बैंकों में लग जाते हैं। इस तरह से वहां पर काम करने वाले लोगों के आदमियों को ही रख लिया जाता है और कोई इम्तिहान नहीं होता है। इसलिए उन में एफीशियेन्सी नहीं है और यही कारण है कि 88 लाख रुपये का घाटा दिखलाया है। उन लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और उस के बाद ही उन को रखना चाहिए। उन को यह पता नहीं है कि सर्विस कैसे की जाती है। बस बैंक मे आ कर बैठ गये। उन को चैक का पता नहीं है और सिलिप का पता नहीं है। उन को डिपोजिटस का पता नहीं है। इसलिए आप को इस को ठीक करना होगा।

उन बेचारों का कुछ पता नही होता है। वे किसी दूसरे आदमी से लिखवाते है, जो चाहे गलत लिखे या सही लिखे, और चाहे खुद ही रुपया निकलवा कर ले जाये। ऐसे फ्राड भी होते हैं। अभी हाल ही मे लन्दन में इस किस्म का जो फ्राड हुआ था, उस के लिए गवर्नमेंट ने 22 लाख रुपया खर्च किया है। ऐसे फ्राड आगे भी होते रहेंगे क्योंकि वे काम

[श्री दरबारा सिंह]

उन लोगों के सुपुर्द हैं, जो बहुत पढ़े-लिखे हैं थोड़े पढ़े-लिखे और देहात के लोगों के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया है कि वे रिजनल लैंग्वेज में कागज पेश कर के बैंक में अपना काम करवा लें।

गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि बैंकों के मुख्तलिफ कारोबार को रिजनल लैंग्वेजिज में करने का काम तीन साल में मुकम्मल हो जायेगा । अगर यह काम तीन साल में पूरा हो जाये, तो यह एक बड़ी अच्छी बात होगी ।

यह जरूरी है कि रूरल एरियाज की तरफ ज्यादा तवज्जुह दी जाये, क्योंकि इस मुल्क में 80 फ़ीसदी लोग देहात में बसने वाले हैं । गवर्नमेंट कामर्शल बैंक्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसायटीज और को-आपरेटिव सोसायटीज को मजबूत करे, लेकिन ग़रीब लोगों को कर्जा जरूर मिलना चाहिए । जो प्रोड्यूस करता है, जो स्माल-स्केल इंडस्ट्री में काम करता है, उस को कर्जा मिलना चाहिए, न कि बड़े बड़े लोगों को, जिन के पास पहले ही से ब्लैक का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है । इस के अलावा अगर गवर्नमेंट डामानटाइजेशन का कदम उठाये, तो मुल्क की फ़िनांशल पोजीशन जरूर अच्छी होगी । गवर्नमेंट को आज, कल या परसों ये स्टेप्स लेने ही होंगे ।

प्राइम मिनिस्टर के 20-पायंट प्रोग्राम में गरीबों के लिए एक गुंजाइश पैदा की है । लेकिन उस का इम्प्लीमेंटेशन कौन करने वाले हैं ? हम नहीं करने वाले हैं । वैसे, अगर हम से करवाया जायेगा, तो हम करेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने यह काम करना है, और वह अभी तक वैसी की वैसी है । सिवाये इस के कि वे लोग वक्त पर दफ़्तर में आ जायें, उन की दिमांगी कैफ़ियत नहीं बदली है । जो लोग काम नहीं करते हैं, उन को शंट आउट करना होगा । बैंक फ़िनांस मिनिस्ट्री के मातहत हैं । मिनिस्टर साहब कम से कम वहां से ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें, जो काम नहीं करते हैं । अभी तक दो बैंकों के हैड्ज़ को निकाला गया है । नये आदमियों को मौका देना चाहिए । एक्सपीरियंस के अलावा इनटेक्रिटी को भी देखना चाहिए कि आया कोई शक्स ग़रीबों का उत्थान करने के बारे में कमिटिड है या नहीं । अभी तक हम ने ऐसी बात नहीं देखी है । बड़ी बड़ी जगहों पर जो लोग बैठे हैं, उन को यह पता नहीं है कि ग़रीब कैसे पिस रहे हैं और कैसे उन की इमदाद करनी चाहिए । नीचे की सतह पर ऐसे लोगों को रखना चाहिए, जो कमिटिड हों, ताकि काम ठीक तरह से चल सके ।

आख़िर में मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को मल्टीपर्पज एजेन्सीज कायम करनी चाहिए, जो इंडस्ट्री, फ़ार्मिन्ग और कर्जों के बारे में सलाह दे सकें । इस बिल के जरिये जो कमीशन बनाया जा रहा है, मैं उस को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरिम स्पीकर साहब, इस में कोई शुबहा नहीं कि जो बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जेरे-ग़ौर है, वह एक अच्छा कदम है । मैं उस के हक और मुआफ़िकत में हूं । इस बिल को देर से लाने की वजह से तालेम-याफ्ता और काबिल लड़कों को जो नुकसान हुआ है, इस बिल में उस की तलाफ़ी की गुंजाइश नहीं है । बैंकों को कोमियाने के बाद इन में जो बहालियां हुई हैं, अगर आप उन की लिस्ट को देखें, तो साफ़ जाहिर होगा कि सिर्फ़ बैंकों के बड़े बड़े अफ़सरों और ऊंचे ओहदेदारों के रिश्तेदारों और रिश्तेदार-दर-रिश्तेदारों की ही बहालियात हो पाई हैं । इस तरह बैंकों के नेशनलाइजेशन का मकसद इस दौरान में कटअन फ़ौत हो चुका है । बहरहाल, देर आयद दुरुस्त आयद ।

मौजूदा बिल के कुछ क्लाजिज पर मुझे सख्त एतराज है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस सिलसिले में तरमीमात लाये, ताकि जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया है, उस से देश को सही मानो में कुछ फ़ायदा हो सके।

अफ़सरशाही का जो चक्कर अंग्रेजों के वक्त से ले कर आज तक जोर-शोर से चल रहा है, हम उसको कम नही कर पाये हैं, बल्कि उसके चगुल मजबूत से मजबूततर हो रहे है। मेरा सब से पहला एतराज क्लाज 3(4) के बारे में है, जिस में कहा गया है :

"The Commission shall have regional offices in such State or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government."

जिस तरह आजादी के 27 साल बाद भी भारत के मुखतलिफ हिस्सों में नदियों के पानी का कजिया अभी तक चल रहा है, उसी तरह इस क्लाज के जरिये रिजनल आफिसिज के एस्टाब्लिशमेंट के बारे में झगड़ा, तनाव और कजिया पैदा होने की खुली छूट दी जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस के बजाय मुल्क को दस यूनिट्स में बांट दिया जाय, और पिछडे हुए हिस्सों, मीडियम लैवल तक डेवेलप्ड हिस्सों और मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड हिस्सों की तीन कैटेगरीज बना दी जायें।

इस क्लाज को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह आगे आने वाले फ़ित्न की जड़ है और आगे चल कर रिजनल आफ़िसिज को एस्टाब्लिश करने के बारे में झगड़ा होगा। इस से बेहतर यही है कि मिनिस्टर साहब अभी इस में तरमीम को मान लें, ताकि आगे चल कर तनाव पैदा न हो, और जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया है, वह पूरा हो सके।

बिहार भी बैकवर्ड स्टेट्स और एरियाज से बाहर नहीं है। आगे चल कर इस क्लाज के जरिये जो नुक्सान होने वाला है, मैं उस को अभी ऐप्रिहैंड कर रहा हूं। आगे आने वाला वक्त बतायेगा कि मेरी शंका और शुबहे में कितनी सदाकत है। अभी मौका है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर कर के इस में तरमीम करें।

इस बिल के क्लाज 4 के प्रोवाइजो पर भी मुझे सख्त एतराज है, जिस मे कहा गया है :

"Provided that as nearly as may be one-half of the members shall be persons who, on the date of their respective appointments, have had experience of not less than ten years in a banking company or in any public sector bank or Reserve Bank or in an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank or a public financial institution."

राजा साहब के मरने के बाद उन का बेटा ही राजा होगा। जम्हूरियत में इस की कतई गुंजाइश नही है। क्या हमारे यहां यूनिवर्सिटीज के प्रोफसर, इकानोमिस्ट और दीगर इकानोमिक एक्सपर्ट नहीं हैं ? जो बैंकों में काम कर चुके हैं, सिर्फ उन्ही को कमीशन के मेम्बर बनाने का प्राविजन रखने की क्या वजह है ? जैसा कि श्री दरबारा सिंह ने कहा है, और क्लाजिज में कमीशन की मेम्बरशिप को सिर्फ एक तबके के लिए मखसस कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि सिर्फ छः कैटेगरीज को फिनांशल इंस्टीट्यूशन माना जायेगा और सिर्फ उन में काम करने वाले लोग ही मम्बरशिप के काबिल समझे गये हैं। मेरा ख़याल है कि इस

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

क्लाज को एमेंड करना चाहिये । मैं मोहतरमा वजीर साहब से कहूंगा कि आप इस में ऐसा प्रावीजन जरूर रखें कि जिस के जरिये एक्सपर्ट को रखा जाय, इकानामिक एक्सपर्टस को रखा जाय, यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर्ज को रखा जाय, दूसरे पढ़े-लिखे लोगों को रखा जाय ।

एक बड़े मजे की बात इस में यह है कि आप ने शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिये गुंजाइश रखी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेम्बर्स की एप्वाइन्टमेंट मे आपने ऐसी गुंजाइश क्यों नहीं रखी ? इस कमीशन के आठ मेम्बर्स होंगे, आप कम्पलसेरिली ऐसा प्रावीजन रखे कि इन आठ मेम्बर्स में से एक मेम्बर शैडयूल्ड कास्ट्स का होगा और दूसरा शैडयूल्ड ट्राइब्स का होगा । मोहतरिम स्पीकर साहब, आप मुझ से एग्री करेंगे—कांस्टीचूशन में इन लोगों के लिये गारन्टी की गई है, उन के लिये परसेन्टेज दी हुई है, हम लोग भी यहां हर रोज इस के बारे में बोलते रहते हैं—लेकिन इस का क्या असर पड़ता है । कांस्टीचूशन मे ऐसा प्रावीजन होने की बिना पर हम इन के लिये कमिटेड है, लेकिन होता कुछ नही है । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस कमीशन में भी एक आदमी शैडयूल्ड कास्ट्स का और एक आदमी शैडयूल्ड ट्राइब्स का रखा जाय और बाई-रोटेशन इस कमीशन का चेयरमैन शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का भी हो । मोहतरिम स्पीकर साहब, आप के जरिये सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस प्रावीजो को ला कर आप ने इस के दायरे को बहुत महदूद कर दिया है । इस का मतलब यही है कि जमीदार मरेगा तो उस का बेटा जमीदार होगा, वह मरेगा तो फ़िर उस का बेटा जमीदार होगा । सैकुलर स्टेट में ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिये । हम लोग अपने अवाम से, अपने मुल्क से, इस के लिये कमिटेड हैं, इसलिये हमारे अवाम की बहबूदी के लिये ऐसी गुंजाइश होनी चाहिये जिस में अवाम और मुल्क का फ़ायदा हो ।

तीसरी चीज—जिस पर मुझे सख्त ऐतराज है—पेज 3 पर क्लाज 4 का सब क्लाज 3 में कहा गया है—The Chairman or any member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years. यह क्या मजाक है—मैं चाहता हूं कि आप इस को तीन बरस कीजिये । एक तरफ आप कहते है कि लोग 55 साल में रिटायर हों, दूसरी तरफ कोरामीन का इंजेक्शन दे कर उन की जिन्दगी को 65 साल तक पहुचाना चाहते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन की बहाली सिर्फ़ 3 बरस के लिये होनी चाहिये और उन की ऐज को 65 से घटा कर 55 साल की जाय, ताकि सर्विसिज के दूसरे लोगों को भी आगे आने का मौका मिल सके ।

इस में मेम्बर्ज की क्वालिफ़िकेशन का जो प्रावीजो रखा गया है—आप जरा उस को भी मुलाहिज़ा फ़रमाइये, इस के बारे मे मुझे एतराज है, सरकार को इस के बारे मे अमेण्डमेंट लाना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक का नुमाइन्दा इस का मेम्बर क्यों नही हो सकता ? एक खास किस्म का तबका ही इस का मेम्बर क्यों हो ? पालिया-मेंट के मेम्बर, असेम्बली के मेम्बर, यूनि-वर्सिटी प्रोफेसर, पी०एच०डी०, ऐसे लोग भी इस के मेम्बर बनाये जायें । आज वक्त बदल चुका है और जितनी तेजी से बदल रहा है, भारत जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है—उस को मद्देनजर रखते हुए वक्त के साथ चलने के लिये कानून में भी तबदीली होनी चाहिये । जब तक कानून अवाम की राय के मुताबिक नहीं होगा, वह अधूरा रह जायगा । उस का सही तौर से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा,

क्योंकि आज जो इम्पलीमेन्टेशन करने वाले हैं, उन को आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, उन का अन्दाजा आप को भी है और मुझे भी है...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उन का हश्र भी यही होगा ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : इसीलिये तो याद दिला रहा हू कि वैसा हश्र न हो । आप इस मे ऐसी अमेण्डमेन्ट्स लाइये जिस से यह अवाम के लिये बन सके और अवाम को फ़ायदा हो ।

आप इस के क्लाज 6 को देखिये—इस को पढने से ऐसा मालूम होता है कि इस बिल को ड्राफ्ट करते वक्त इस का कतई ख्याल नही रखा गया है । इस में जो बात रखी गईहै, मैं उसे को आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—'6(1) The Central Government may remove from the office the Chairman or any member.....' यह बिलकुल स्टीरिओ-टाइप चीज है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस मे ऐसा क्लाज क्यो नही रखा गया कि सब ऐसे लोग जिन का पोलिटीकल एफ़िलिएशन ऐसी जमायतों के साथ हो, जिस की रस्सी दूसरे मुल्क में है, वहां से रस्सी खीचते है तो यहां घन्टी बजने लगती है— ऐसे लोगों को इस में नही रखा जायगा । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं—आप के ही वित्त विभाग मे एक साहब हैं, जो एक बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिन का ताल्लुक आनन्द मार्ग से है । पिछले साल उन की बेगम ने डेढ लाख रुपया जमा कर के आनन्द मार्ग को दिया है । मेरे पास सुबूत है, मैं कोई जुबानी बात नही कह रहा हूं, आप के वित्त विभाग में ऐसा हुआ है—

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I would like to say that instead of taking the names of the officers who are not in a position to defend themselves here, I would request the hon. Member that, if he has any specific allegations, he may send them with all the particulars to me. I shall certainly look into them.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैंने नाम नहीं लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मोहतरिम, आप जरा मेरी तरफ भी तवज्जह फरमाइये । यह जो आप का जाब्ता है, इस में लिखा हुआ है कि जब किसी की तरफ कोई ऐसा इल्जाम लगाना हो तो उस का नाम पहले से सदर को दिया जाता है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैंने नाम नही लिया है । मैंने कहा है कि एक अफ़सर हैं, जो चेयरमैन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फ़िर मोहतरिमा क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आया है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मोहतरिमा ने कहा है कि नाम भेजिये, लिख कर भेजिये ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो कोई झगडा नही है—बात साफ है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैं यही अर्ज कर रहा था कि क्लाज 6 में एक क्लाज ऐसा होना चाहिये कि ऐसे आदमियों की बहाली मेम्बरशिप के लिये या चेयरमैनशिप के लिये नही होगी जिन का एफिलिएशन किसी ऐसी जमायत के साथ होगा, जो एन्टीनेशनल एक्टिविटीज (anti-national activities) में हिस्सा लेती होगी । यह ध्यान में रखने की चीज है—मोहतरिम स्पीकर साहब, आज

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

कल आप भी शान्ति में हैं और अल्लाह के फज्ल से हम लोग भी शान्ति में चल रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कभी शान्ति में नहीं रहा हूं, यह तो इत्तिफाक की बात है कि शान्ति मिल रही है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : जी हां यह इत्तिफाक की बात है कि हम लोग भी शान्ति से अपनी बात सुना रहे हैं ।

इसी सिलसिले की एक कड़ी में और अर्ज करना चाहता हूं—आप इस को लागू करेंगे तो देश को फायदा होगा, देश तबाह होने से बचेगा । देश में कुछ लोग चाहते हैं कि देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं, देश की अवाम तबाह हो जाये, देश खत्म हो जाय, लेकिन इस तरह की कार्यवाही से देश को बचाया जा सकेगा, हमारा देश सुरक्षित रह सकेगा । लेकिन ऐसे लोगों को आप को स्क्रूटिनाइज करना होगा, उन को हटाना होगा, जो आप की कुर्सी पर बैठ कर अवाम की गर्दन को उड़ा रहे हैं, देशद्रोहीपन का सुबूत और मजाहरा खुले कर रहे हैं ।

इसी तरह से क्लाज 8 के बारे में मेरा यह आब्जैक्शन है कि इस में ऐसे लोगों को लिया जाय जो बैंकिंग इस्टीचूशन्स की तरक्की के लिये कमिटेड हों, जो अवाम की भलाई कर सकें । बैंकों के नेशनलाइजेशन का मतलब यही था कि हम अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें । पहले कुछ पूंजीपति आपस में मिल कर बैंकों से फायदा उठा लेते थे अवाम को बैंकों से कोई फायदा नहीं मिलता था । बैंकों के नेशनलाइजेशन का मकसद यह था कि मुल्क की 60 करोड़ जनता जो गांवों में रहती है, उस को फायदा हो, जैसे स्माल फार्मर्स हैं, स्माल इण्डस्ट्रीज वाले लोग हैं, उन को फायदा हो, वे अपनी इण्डस्ट्रीज गांवों में लगायें ताकि गांवों की जनता को एम्पलायमेन्ट मिल सके ।

आखिर में, मैं यही अर्ज करूंगा कि क्लाज 13 को बिल्कुल डिलीट किया जाना चाहिये ।

मेरी आप के जरिये दरख्वास्त है कि क्लाज 13 को बिल्कुल डिलीट किया जाना चाहिए । मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं । मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं :

"It shall not be necessary to consult the Commission in regard to the selection of a person—

(a) for appointment to a post in the clerical or allied cadre, on compassionate grounds (in pursuance of the scheme framed by a public sector bank in consultation with the Commission and with the previous sanction of the Central Government), of a dependent of an employee who had died while in the service of the public sector bank;"

इसी तरह से और क्लाजेज हैं । मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इसके जरिए से आप एम्प्लाइज को खुली रस्सी दे रहे हैं कि जितना ही खींचो उतनी ही मजबत होती जायेगी । भारत में जितने कार्पोरेशन बने हैं, ऐसा मालूम होता है कि वे किसी को भी जवाबदेह नहीं हैं । न तो पार्लियामेंट के लिए वह जवाबदेह हैं और न अवाम के लिए जवाबदेह हैं हालांकि अवाम के लिए ही सारे कार्पोरेशन्स को बनाया गया है । फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, इंडियन आयल कार्पोरेशन, सी ड कार्पोरेशन, जूट कार्पोरेशन—इनके बारे में जितना ही कम कहा जाये वही अच्छा है । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन बैंकों का जो सही मकसद है, अवाम के मफाद के लिए हों, यह बात उसूली तौर पर तय है तो इसको

अमल में भी लाना चाहिए । उसको लागू भी करना चाहिए । बैंक कुछ लोगों के लिए ही फायदेमन्द न होकर अवाम के लिए भी फायदेमन्द हों ।

इन सब बातों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं चाहता हूं सरकार मेरे सुझाव पर ध्यान दे, यह बिल अवाम का बिल बने, किसी खास तबके के लिए ही यह बिल बनकर न रह जाये ।

شری محمد جمیل الرحمان

(کشن گنج): محترم اسپیکر صاحب- اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینکنگ سروسز کمیشن بل زیر غور ہے وہ ایک اچھا قدم ہے- میں اس کے حق اور موافقت میں ہوں- اس بل کو دیر سے لانے کی وجہ سے تعلیم یافتہ اور قابل لڑکوں کو جونقصان ہوا ہے- اس بل میں اس کی تلافی کی گنجائش نہیں ہے- بینکوں کو قومیانے کے بعد انہیں جو بحالیاں ہوئی ہیں- اگر آپ ان کی لسٹ کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ صرف بینکوں کے بڑے بڑے افسروں اور ان کے رشتے داروں اور رشتیدار- اور رشتیداروں کی ہی بحالی ہو پائی ہے- اس طرح بنکوں کے نیشنلائزیشن کا مقصد اس دوران میں قطعاً فوت ہو گیا- بحر حال دیر آید درست آید-

موجودہ بل کے کچھ کلاز پر مجھے سخت اعتراض ہے- اور میں چاہونگا

کہ سرکار اس سلسلہ میں ترمیمات لائے - تاکہ جس مقصد کے لئے یہ بل لایا گیا ہے اس سے دیش کو صحیح معنوں میں کچھ فائدہ ہو سکے-

افسر شاہی کا جو چکر انگریزوں کے وقت سے لیکر آج تک زور شور سے چل رہا ہے- ہم اس کو کم نہیں کر پائے ہیں- بلکہ ان کے چنگل مظبوط سے مظبوط تر ہورہے ہیں- میرا سب سے پہلا اعتراض کلاز ۳ (۴) کے بارے میں ہے- جس میں کہا گیا ہے-

"The Commission shall have regional offices in such State or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government."

جس طرح آزادی کے ۲۷ سال بعد بھی بھارت کے مختلف حصوں میں ندیوں کے پانی کا قصہ ابھی تک چل رہا ہے- اس طرح اس کلاز کے ذریعہ ریجنل آفیسز کے ایسٹیبلشمینٹ کے بارے میں چھکوا تناؤ اور قضیہ پیدا ہونے کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے- میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بجائے ملک کو دس یونٹس میں بانٹ دیا جائے اور بچھڑے ہوئے حصوں- مڈیم لیول تک ڈویلپ حصوں اور موسٹ انڈسٹریل لائزڈ حصوں کی تین کیٹگریز بنادی جائیں -

[شری محمد جمیل الرحمان]

اس کلاز کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں کی جڑ ہے۔ اور آگے چل کر ریجنل افسر کو اسٹیبلش کرنے کے بارے میں جھگڑا ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ منسٹر صاحب ابھی اس میں ترمیم کو مان لیں۔ تو آگے چل کر اس میں تناؤ پیدا نہ ہو۔ اور جس مقصد کے لیے یہ بل لایا گیا ہے وہ پورا ہو سکے۔

بہار بھی بیکورڈ سٹیٹ اور ایریا سے باہر نہیں ہے۔ آگے چل کر اس کلاز کے ذریعہ جو نقصان بہار کو ہونے والا ہے - میں اس کو ایپریشیئٹ کررہا ہوں۔ آگے آنے والا وقت بتلائیگا کہ میری شنکا اور شبہہ میں کتنی صداقت ہے۔ ابھی موقعہ ہے کہ منسٹر صاحب اس پر غور کرکے اس میں ترمیم کریں۔ اس بل کے کلاز ۲ کے پرووژن پر بھی مجھے سخت اعتراض ہے۔ جس میں کہا گیا ہے :

"Provided that as nearly as may be one half of the members shall be persons who, on the date of their respective appointments, have had experience of not less than ten years in a banking company or in any public sector bank or Reserve Bank or in an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank or a public financial institution."

راجہ صاحب کے کرنے کے بعد ان کا بیٹا ہی راجہ ہوگا۔ جمہوریت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا ہمارے یہاں یونیورسٹی کے پروفیسر اکنامسٹ اور دیگر اکونومک ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ جو صرف بینکوں میں کام کر چکے ہیں صرف انہی کو کمیشن کے ممبر بنانے کا پرووژن رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ جیسا کہ شری دربارہ سنگھ نے کہا ہے - اور کلاز میں کمیشن کی ممبرشپ کو صرف ایک طبقے کے لئے مخصوص کردیا گیا ہے۔ ایکسپلینیشن میں کہا گیا ہے کہ صرف چھ کیٹیگریز کو فائننشل انسٹیٹیوشن مانا جائیگا اور صرف ان میں کام کرنے والے لوگ ہی ممبرشپ کے قابل سمجھے جائینگے - میرا خیال ہے کہ اس کلاز کو امینڈ کرنا چاہئیے -

میں محترمہ وزیر صاحب سے کہونگا کہ آپ اس میں ایسا پرووژن ضرور رکھیں کہ جس کے ذریعے ایکسپرٹ کو رکھا جائے - اکانومک ایکسپرٹ کو رکھے جائے - یونیورسٹی پروفیسرز کو رکھا جائے - دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو رکھا جائے -

ایک بڑے مزے کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے شڈولڈ کاسٹ اور شڈولڈ ٹرائبز کے لئے گنجائش رکھی ہے - لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ممبرز کی اپائنٹمنٹ میں آپ نے ایسی گنجائش کیوں نہیں رکھی - اس کمیشن کے آٹھ ممبر ہونگے - آپ

کمپلسری ایسا پرووزن رکھیں کہ ان آٹھ ممبرز میں سے ایک ممبر شڈولڈ کاسٹ کا ہوگا - اور دوسرا شڈولڈ ٹرائبس کا ہوگا - محترم سپیکر صاحب آپ مجھ سے ایگری ہونگے کہ کانسٹیٹیوشن میں ان لوگوں کے لئے گارنٹی دی گئی ہے - ان کے لئے پرسنٹیج دی ہوئی ہے - ہم لوگ بھی یہاں پر ہر روز اس کے بارے میں بولتے رہتے ہیں - لیکن اس کا کیا اثر پڑتا ہے - کانسٹیٹیوشن میں ایسا پرووزن ہونے کی بنا پر ہم اس کے لئے کموٹڈ ہیں - لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے - اس لئے میں چاہتا ہوں - کہ اس کمیشن میں بھی ایک آدمی شڈولڈ کاسٹ کا اور ایک آدمی شڈولڈ ٹرائبس کا رکھا جائے اور باقی روٹیشن اس کمیشن کا چیئرمین شڈولڈ کاسٹ اور شڈولڈ ٹرائبس کا بھی ہو - محترم سپیکر صاحب آپ کے ذریعے سرکار سے میری گذارش ہے کہ اس پرووزو کو لیکر آپ نے اسکے دائرے کو بہت محدود کر دیا ہے - اس کا مطلب یہی ہے کہ زمیندار مرے گا تو اس کا بیٹا زمیندار ہوگا - وہ مرے گا تو پھر اس کا بیٹا زمیندار ہوگا - سیکولر سٹیٹ میں ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہئیے- ہم لوگ اچھے عوام سے - اچھے ملک سے اس کے لئے کموٹڈ ہیں - اس لئے ہمارے عوام کی بہبودی کے لئے ایسی گنجائش ہونی چاہئیے جس میں عوام اور ملک کا فائدہ ہو

تیسری چیز جس پر مجھے سخت اعتراض ہے - پیج ۳ پر کلاز ۴ ڈ سب کلاز ۳ میں کہا گیا ہے - یہ کیا مذاق ہے - میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تین برس کیجئے- ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ ۵۵ سال میں ریٹائر ہوں دوسری طرف کورامین کا انجیکشن دے کر ان کی زندگی کو ۶۵ سال تک پہنچانا چاہتے ہیں - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بحالی صرف ۳ برس کے لئے ہونی چاہئیے- اور ان کی ایج کو ۶۵ سے گھٹا کو ۵۵ سال کی جائے تاکہ سروسز کے دوسرے لوگوں کو بھی آگے آنے کا موقع مل سکے -

اس میں ممبرز کی کوالیفیکیشن کا جو پرووزن رکھا گیا ہے - آپ ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے - اس کے بارے میں مجھے اعتراض ہے - سرکار کو اس کے بارے میں امینڈمینٹ لانی چاہئیے - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پبلک کا نمائندہ اس کا ممبر کیوں نہیں ہو سکتا - ایک خاص قسم کا طبقہ ہی اس کا ممبر کیوں ہو - پارلیمنٹ کے ممبر - اسمبلی کے ممبر - یونیورسٹی پروفیسرز - پی ایچ ڈی ایسے لوگ بھی اس کے ممبر بنائے جائیں - آج وقت بدل چکا ہے -

[شری محمد جمیل الرحمان]

اور جتنی تیزی سے بدل رہا ہے - بھارت جتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے - اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ چلنے کے لئے قانون میں بھی تبدیلی لانی چاہئے - جب تک قانون عوام کی رائے کے مطابق نہیں ہوگا - وہ ادھورا رہ جائے گا - اس کا صحیح طور سے ایمپلیمینٹیشن نہیں ہوگا - کیونکہ آج جو ایمپلیمینٹیشن کرنے والے ہیں - ان کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں - ان کا اندازہ آپ کو بھی ہے اور مجھ کو بھی ہے -

شری رام اوتار شاستری: ان کا حشر بھی یہی ہوگا -

شری محمد جمیل الرحمان : اس لئے تو یاد دلا رہا ہوں کہ ویسا حشر نہ ہو - آپ اس میں ایسی امینڈمینٹ لائیے - جس سے یہ عوام کے لئے بن سکے - اور عوام کو فائدہ ہو -

آپ اس کے کلاز 6 کو دیکھئے - اس کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے - کہ اس بل کا ڈرافٹ کرتے وقت اس کا قطعی خیال نہیں رکھا گیا ہے - اس میں جو بات رکھی گئی ہے - میں اس کو آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں -

The chairman or any member shall held office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years.

یہ بالکل سٹیریو ٹائپ چیز ہے - میں پوچھنا چاہتا ہوں - کہ اس میں ایسا کلاز کیوں نہیں رکھا گیا کہ سب ایسے لوگ جن کا پالیٹیکل افیلیشن ایسی جماعتوں کے ساتھ ہو - جس کی رسی دوسرے ملک میں ہے - وہاں سے رسی کھینچتے ہیں - تو یہاں گھنٹی بجنے لگتی ہے - ایسے لوگوں کو اس میں نہیں رکھا جائے - میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں - آپ کے ہی ایک بھاگ میں ایک صاحب ہیں - جو ایک بورڈ کے چیرمین ہیں - جن کا تعلق آنند مارگ سے ہے - پچھلے سال ان کی بیگم نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ جمع کرکے آنند مارگ کو دیا میرے پاس ثبوت ہے - میں کوئی زبانی بات نہیں کہہ رہا ہوں - آپ کے وت وبھاگ میں ایسا ہوا ہے -

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I would like to say that instead of taking the names of the officers who are not in a position to defend themselves here I would request the hon. Member that, if he has any specific allegations, he may send them with all the particulars to me. I shall certainly look into them.

شری محمد جمیل الرحمان : میں نے نام نہیں لیا ہے -

ادھیکش مہودے : آپ ذرا میرے طرف بھی توجہ فرمائیے - یہ جو آپ کا ضابطہ ہے - اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کی طرف کوئی ایسا الزام لگاتا ہو تو اس کا نام پہلے سے صدر کو دیا جاتا ہے -

شری محمد جمیل الرحمان : میں نے نام نہیں لیا ہے - میں نے کہا ہے کہ ایک افسر ہے - جو چیرمین ہے -

صدر مہودے : پھر محترمہ کیا کہہ رہی ہیں - مجھے سمجھ نہیں آیا ہے -

شری بھگوت جھا آزاد : محترمہ نے کہا ہے کہ نام بھیجئے - لکھ کر بھیجئے -

ادھیکش مہودے : پھر تو بات صاف ہے - کوئی جھگڑا نہیں ہے -

شری محمد جمیل الرحمان : میں یہی عرض کر رہا تھا - کہ کلاز 7 میں ایک کلاز ایسا ہونا چاہئے ، کہ ایسے آدمیوں کی بحالی ممبر-شپ کے لئے یا چیرمین شپ کے لئے نہیں ہوگی - جن کا ایفیلیشن کسی ایسی جماعت سے تعلق ہوگا جو اینٹینیشنل ایکٹیویٹیز (*anti-national activities* میں حصہ ہے - وہ دھیان میں رکھنے کی چیز ہے - محترم سپیکر صاحب - آج کل آپ بھی شانتی میں ہیں - اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ بھی شانتی میں چل رہے ہیں -

ادھیکش مہودے : میں تو کبھی شانتی میں نہیں رہا ہوں - یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ شانتی مل رہی ہے -

شری محمد جمیل الرحمان : یہ اتفاق کی بات ہے - کہ ہم لوگ بھی شانتی سے اپنی بات سنا رہے ہیں-

اس سلسلے کی کڑی میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں - آپ اس کو لاگو کریںگے تو دیش کا فائدہ ہوگا - دیش تباہ ہونے سے بچےگا - دیش میں کچھ لوگ چاہتے ہیں - کہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دیش کے عوام تباہ ہو جائیں، دیش ختم ہو جائے - لیکن اس طرح کی کارروائی سے دیش کو بچایا جا سکے گا ہمارا دیش سرکشت رہ سکیگا - لیکن ایسے لوگوں کو آپ کو سکیورٹیفائیز کرنا ہوگا - ان کو ہٹانا ہوگا - جو کرسی پر بیٹھ کر عوام کی گردن کو اڑا رہے ہیں - دیش ودھروھی پن کا ثبوت اور مظاہرہ کھلے عام کر رہے ہیں -

اسی طرح سے کلاز 8 کے بارے میں میرا اوبجیکشن ہے - کہ اس میں آپ کو

[شری محمد جمیل الرحمٰن]

ایسے لوگوں کو لیا جائے - جو بینکنگ انڈسٹریز کی ترقی کے لئے کمیٹڈ ہوں - جو عوام کی بھلائی کر سکیں - بینکوں کے نیشنلائزیشن کا مطلب یہی تھا کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں - پہلے کچھ پونجی پتی پنس میں ملکر بینکوں سے فائدہ اٹھا لیتے تھے - عوام کو بینکوں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا - بینکوں کے نیشنلائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ ملک کی ساٹھ کروڑ جنتا جو گاؤں میں رہتی ہے - اسکو فائدہ ہو - جیسے سمال فارمرز ہیں - سمال انڈسٹریز والے ہیں - ان کو فائدہ ہو - وہ اپنی انڈسٹریز گاؤں میں لگائیں تاکہ گاؤں کے لوگوں کو ایمپلائمنٹ مل سکے -

آخر میں میں یہی عرض کرونگا - کلاز ۱۳ کو بالکل ڈلیٹ کیا جانا چاہئے میری آپ کے ذریعے درخواست ہے - کہ کلاز ۱۳ کو بالکل ڈلیٹ کیا جانا چاہئے - میں بالکل اس کے حق میں ہوں - میں آپکی جانکاری کے لئے صرف ایک لائین پڑھنا چاہتا ہوں -

"It shall not be necessary to consult the Commission in regard to the selection of a person—

(a) For appointment to a post in the clerical or allied cadre, on compassionate grounds (in pursuance of the scheme framed by a public sector bank in consultation with the Commission and with the previous sanction of the Central Government), of a dependent of an employee who had died while in the service of the public sector bank."

اسی طرح سے اور کلازز ہیں - میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں - کہ اس کے ذریعے سے آپ ایمپلائیز کو کھلی رسی دے رہے ہیں کہ جتنی ہی کھینچو اتنی ہی مضبوط ہوتی جائیگی - بھارت میں جتنے کارپوریشن بنے ہیں - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں - نہ تو پارلیمنٹ کے لئے وہ جواب دہ ہے حالانکہ عوام کے لئے ہی سارے کارپوریشن کو بنایا گیا ہے - فرٹیلائیزر کارپوریشن - انڈین آئیل کارپوریشن - سیڈ کارپوریشن - جیوٹ کارپوریشن - ان کے بارے میں جتنا ہی کم کہا جائے - وہی اچھا ہے - اس لئے میری گزارش ہے کہ ان بینکوں کا جو صحیح مقصد ہے عوام کے مفاد کے لئے ہیں - یہ بات اصولی طور پر طے ہے - تو اس کو عمل میں بھی لانا چاہئے - اس کو لاگو بھی کرنا چاہئے - بینک کچھ لوگوں کے لئے ہی فائدے مند نہ ہو کر عوام کے لئے بھی فائدے مند ہوں -

ان سب باتوں کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں - میں چاہتا ہوں کہ سرکار میرے سجھاؤ پر دھیان دے - یہ بل عوام کا بل بنے، کسی خاص طبقے کے لئے ہی یہ بل بن کر نہ رہ جائے -]

SHRI ARAVINDA BALA PAJANOR (Pondicherry): Mr. Speaker, Sir, I support this piece of legislation. It has come in correct time to regulate these financial institutions. In this line it is similar to that of UPSC. It is a welcome thing. The hon. Members referred to the point as to how these banks are functioning in the rural sectors and also expressed their view that people with certain amount of experience in rural life should only be sent there. They referred to the provision of ten years of experience to be a member of the Commission. I am afraid how people from the rural sector can have ten years of banking experience. Our experience also tells us that people who are in the urban areas are reluctant to go to rural areas and even if they are sent in the rural areas they try to impose the conditions that are available in the cities with the results that the benefits intended to be rendered by the banking institutions to the common man are not reaching him in the rural areas Therefore, Sir, when the recruitment rules are framed under this Commission they must also see that the agricultural needs of our country and the service conditions be so moulded so as to meet this requirement.

Now, a word about promotion in the banking institutions Promotions for junior officers are given and there is reservation of 25 per cent from clerical grade. I urge that similar provision must be made for clerical posts from the attendants and the subordinate class IV officers. There are graduates and final school pass persons working as attendants and class IV servants.

Sir, the banking institutions are now functioning in closed chambers. Though we may claim that we are going to the people and a number of new branches are being opened in villages yet the common man is not very much benefited by this. The Service Commission is having supervisory power and the supervisory power alone is not sufficient to extend the services of the banks to the rural areas. Therefore, the banks that are in rural areas must be governed by a separate Commission or by a Committee within the Commission itself. My fear is if the Banking Commission is to follow the same procedures involving voluminous files as are followed in UPSC, the same pitfalls that are available in UPSC will come to this Commission. It is a good thing to bifurcate these services into Commission so that efficient work can be done but if you are going to follow the same procedure as is available in UPSC then only in name we will have the Commission but not in execution. Therefore, Sir, when we introduce these pieces of legislation they must be made on certain specific lines. I find in the entire law the common law language is used and the language is not specific. I wish the Government to fill up the loopholes at least by referring it to certain specialists.

Eighty-five per cent of our population lives in the rural sector. The banking institution is a vital thing that controls—though we say it finances—the very life of our country. Therefore, we must contemplate in such a way that these Commissions function in those areas with efficiency, zeal and real spirit. But in this Bill I find only solutions that are given to the banking institutions to be controlled mostly in urban areas. If there is some piece of legislation by which we can think of the rural sector in banking institutions then we can render real service to the rural people.

When some hon. Members expressed their doubts that these financial institutions are helping big industrialists and the big farmers, I feel, because of the supervisory power that is given to the Commission if it is not properly exercised it will go down

[Shri Aravinda Bala Pajanor]

still further and deteriorate still further. Though it is said that poor people are being helped yet many of us know that only those people who have some influence are alone benefited as there are a number of loopholes. If these loopholes are not plugged, we may repeat the past tragedy. Therefore, I request that after the appointment of the Commission the rules must be framed as early as possible. Then, they must be sent to these institutions. In this connection, it is also said that the other financial institutions may also be brought in, whenever the Central Government feels the necessity for it.

In our country, especially in the southern parts, there is an alarming situation because of the operation of the chit fund companies. They are also financial institutions. They are making lot of profits. I do not know whether this Commission will extend its supervisory power or its advisory power or its controlling power to these institutions. There are a number of chit fund companies in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and also in Pondicherry. These institutions are now controlled by certain legislations of the States. When the question was raised that it was a Central subject, it was said that these are not banking institutions, and therefore, they do not come under the Central Government. In my opinion—it is the opinion of most of the people—they function more like banks. They finance people, collect money from people, they distribute a portin to the people and they themselves devour most of the money. These institutions must be controlled. The State legislations are not sufficient to control these institutions. There are similar institutions in other parts of the country also. For example, there are hire purchase companies and money lending institutions. In these institutions, there are many people who are working without any experience in finance. Sir, if these institutions are allowed to function freely, they will hamper the very structure of our financial status. They inject money into the society, they sometimes take money from the society and they control a viable portion of our economy. This is a fact known to many of us. But, we are not bringing forward any legislation to control these institutions. These institutions form a major sector of the financial transactions of our people. Day in and day out, people are having regular contacts with these types of institutions and these institutions dominate the monetary position of a very large number of our people. Forty per cent of our people go to these chit funds and bid chits and they also make contributions to these companies. They are very much connected with these institutions in so far as their financial transactions are concerned. Then, there are a number of hire purchase companies. They are financial institutions, according to me. Ten per cent of our people purchase articles and other things from these companies. These companies take money from these big institutions and practically wreck the economy of our country. Therefore, Sir, I submit that this Banking Service Commission should not stop only with these financial institutions that are recognised by our laws, but they should also control these institutions which are actually ruining the common people. The services in these institutions must also be controlled. For example, I know two or three companies in our side. They are family concerns. They have a big name and they recruit people who are not even qualified in the third standard. In other institutions, 300—400 people are recruited and in some places, there are thousands of people employed in such institutions. Because the service conditions and the status of the people employed therein are not regulated, a number of malpractices are taking place in such companies.

When we speak about nationalised banks, we say that they are not functioning properly and that the customer service has deteriorated after nationalisation. I do agree with that. I have also the sad experience when I had been to a nationalised bank along with my friend to deposit a certain sum There, we were made to wait for four hours. This is the position in some of the institutions. But, that cannot be regulated simply by a piece of legislation like this Unless you have a goal, unless you have a regulation to control all these institutions, it cannot be done. But the case is still worse in the case of those institutions which are functioning as a by-product of the banking institutions. Therefore, when we have this legislation, we must also look at the other sectors of this business which do not come within the ambit of this legislation. Now that we are in an emergency, this is the time for us to consider these institutions which do not come within the ambit of this Bill and provide for them also. I do not know whether it is by a clever method that they have escaped this kind of legislation. Therefore, I request the authorities here to consider this aspect very seriously and try to bring within the legislation, within the scope of the Banking Service Commission all such institutions and render this service to the people.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): I rise to support the Bill. In this Bill, there is nothing new by way of a fresh policy. The setting up of a Banking Service Commission for the purpose of recruitment and appointment of banking personnel is just a logical step in the line of logistics following the nationalisation of banks. With respect to the Railways and other public sector areas, this is the policy we have adopted. Therefore, it is only legitimate and natural that the banking personnel must also be recruited by a Banking Service Commission.

It will, in fact, be appreciated that the most predominant factor in banking is the personal service we get. It is not like other manufacturing industries where so many other factors count; in banking it is the personal service that counts most. The success or failure of the institution depends on the type of people who serve in the banks.

12.00 hrs.

I do not want to go into the different clauses of the Bill because strictly this is not the stage for it. I should, however, try to have a look at the broad principles and certain factors that have come into the public gaze taking into account our experiences during the period since the nationalisation of banks. It is now common knowledge and admitted almost everywhere that whatever be the justification somebody may offer, the banking industry, the nationalised sector of it and the other sector, has not acquired in the course of the last few years what may be called an impression or assessment of reputation. It had the 'distinction' to be singled out by the Prime Minister during her speech when she said that if the persons employed in the nationalised sector do not properly behave, they can bring dis-service to the people and ill-fame to the idea of nationalisation. Now it is known—at least that is the assessment of the people at large—that banking has become a cesspool of nepotism, to some extent corruption, and misbehaviour by persons who are serving in the banks. You have got arrogance there, you find insolence there, absolute irresponsibility in certain quarters and a total lack of appreciation of the motivation that prompted Government to launch on the measure of nationalisation. I wish that on the debate in this House on this subject of banking, no censorship was imposed, because if only the persons serving in the banks knew how this House and the members of this House have appreciated their service, it would have been a dose for them for a certain measure of corrective behaviour in the future. That is all I could say about it. They have got

[Shri C. M. Stephen]

high wages; they are being treated as a privileged class among employees in industry. In the banking industry you find overtime much more than anywhere else. For doing clerical work for which they are engaged, there is abnormal overtime inspite of the high wages they are paid. And that is accepted as a normal thing in the banking industry. Stories are afloat that loans were being given by certain officers knowing that the loans would be irrecoverable, with a definite understanding that the loans might be written off at a particular stage as bad debt. I do not want to make any particular reference to any branch but stories have come in that certain employees collected commission on the basis of loans granted and that that commission was shared among the bank staff. This is what we are experiencing and the customer does not get a proper service. Even those customers who have deposited their money in the banks and who have got to deal with the banks get a service which is not of a high order. I repeat that there is distinction between the manufacturing industry and the banking industry the difference is that in the banking industry from beginning to end the overall thing is the service that you get. If the service is vitiated then the experiement fails. Bank nationalisation had two purposes: to take away the money power from certain quarters and vest it back in the public area and the other was to use the savings of the people for regeneration of wealth in this country and get it to the poor man and get better service for the general public. The second part has totally failed. This is the assessment of the common man and it is the common man's impression that was reflected in the remarks of the Prime Minister when she made a survey of the economic situation in this country. I do not know how far this has been taken note of. This malady has to be rectified. Will it be rectified merely by recruiting the proper type of people? At the stage of recruitment a person is absolutely perfect but once into it, once his tenure seems to be assured, circumstances are such that he can lord over everybody; even the best person starts degenerating. You may try to recruit the best people. Subsequently the fact has to be taken into account that in the banking industry there are trade unions. Those unions are not affiliated to the central organisation but they are known to have their sympathies with them. Unlike other industries there is collusion between the so-called leadership of the trade union front and the so-called managers who are in control of the industry. Industrial peace can easily be had if this arrangement is cultivated—arrangement whereby collection of commission is permitted and distributed, arrangement whereby recruitment is made at the dictates of the union, arrangement whereby victimisation could be inflicted by transfers, arrangement whereby favouritism could be shown by keeping particular persons in particular area and no transfer being effected. If there is to be collusion like this, what is the industrial peace worth? There is a third factor, that is, the people at large, people who are dealing with it. If banks are allowed to have this sort of arrangement and people are allowed to be fleeced and service, is vitiated what purpose has it served? That is the total experience that is given. I am happy that the Labour Ministry is represented here today in full force. Shri Raghunatha Reddy was here; he had just gone out. Well, now, we are trying to revamp the entire section. A new concept is also now sought to be injected into the whole sphere, that is to say, it is not the employer and the employees alone who count, it is not the management and the workers alone who count but there is a third factor also. The third factor is the community, the people. That third factor must also be there. Now, a concept is developing that the Industrial Committees must be there, there must be an apex body to take care of the total policy in the country and below that with respect to different

industries there must be industrial committees taking stock of the situation in different industries and to giving directions there limiting not merely to the management labour relations but something higher and something larger. With this view, an attempt is being made, an effort is being made. My understanding is that in the banking industry there was a conference where the Government, the banking management, Finance Ministry and the national trade union leaders were also present and there was an agreement reached that an industrial committee should be formed. But I come to understand that an effort is being made to scuttle that agreement. I would like to know—of course during this session I may not able to know —what exactly the reaction of the Labour Ministry to this is, Banking industry is not something with which somebody can play. Nor the Labour Ministry can afford to permit it to play with it. I would like to draw the attention of the Labour Minister, Mr. Verma, to the fact that the whole purpose of this bill is to improve the conditions and to improve the serviceability of the institutions and I would like to point out that by mere recruitment serviceability would not come, serviceability would come only if they can set up this committee whereby apart from the management and the workers, the community is also taken into account. With that, the industrial committees were thought of in the textiles industry also. So in the banking conference there was a move to set up an industrial committee. That is my information. Subsequently, a move is being made to scuttle this idea. I would like to know what the reaction of the Labour Ministry is. On the floor of this House, I want to make an emphatic announcement, as a representative of the major trade union movement of this country, if this industrial committee for the banking is going to be scuttled by anybody take it from me that there will be no industrial committee in any other sector also. Let not partisanship and factionalism come into the picture. I am saying this with all seriousness. Let it be remembered the persons in authority who are guiding the bureaucrats, who are in the national front, who are in the labour front are not persons who can react also. We can understand things and we know how to tackle things. But let not any attempt be made to scuttle this move. This is my humble submission. If this bill is to have its proper effect, then the subsequent stages may also be taken into account and by the subsequent stages, I mean, a proper national set up whereunder the working of the banks could be reviewed, could be kept under surveillance policies can be evolved and policies can be implemented so that the banking institutions may not become the happy hunting ground for some people at the expense of the general public. If that is done, the logistic whereunder nationalisation was effected, whereunder this bill is brought about, will have its proper effect as far as the people at large are concerned. This is what I have got to say with reference to the Bill. I support the Bill and I hope this will be a deviation from the *status quo* arrangement and it will bring about better integrity, better efficiency and better serviceability for the institutions, for the people at large and nationalisation will be taken to its logical conclusion keeping in view the purpose for which the banks were nationalised. With these words I support this motion.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, कई मित्रों ने इस विधेयक में कई प्रकार की त्रुटियां बतलाने की कोशिश की है । उन त्रुटियों के बावजूद यह विधेयक कुछ काम का है । इसलिए मैं इस का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

यह बैंकिंग सेवा आयोग जिस का गठन करने की बात इस विधेयक में की गई है, उस के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं । मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि इस आयोग में ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए जिन की आस्था आप की नीतियों

[श्री रामावतार शास्त्री]

में हो, सरकारी क्षेत्र सफलीभूत हो, राष्ट्रीयकृत संस्थाएं आगे बढ़े, जिन का विश्वास इस में हो, जिन का विश्वास धर्मनिरपेक्षता की नीति में हो, जिन का विश्वास समाजवाद में हो और जिन का विश्वास जनतान्त्रिक प्रणाली में हो, ऐसे ही लोगों को इस आयोग में सदस्य बनाया जाना चाहिए। अगर यह लोग इस तरह के होंगे तो जाहिर बात है कि जिन कर्मचारियों को यह नियुक्त करेंगे, उन कर्मचारियों में ऐसे ही लोग भर्ती किये जायेंगे जिन का विश्वास इन सिद्धान्तों के प्रति होगा। अभी स्थिति दूसरी है। जो बैंकों के बड़े बड़े अफ़सरान हैं, बड़े बड़े कर्ताधर्ता हैं, जो नौकरशाह हैं, उन का न जनता से सम्बन्ध है और न बैंकों के कर्मचारियों से सम्बन्ध होता है। उन की दुनिया कोई तीसरी ही होती है और यही वजह है कि बहुत जगहों पर ठीक से काम नहीं हो पाता है। मजदूरों और कर्मचारियों और प्रबन्धकों में समय-समय पर झगड़े आमतौर पर होते रहते हैं और काम में नुक्सान होता है। मैं इस के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। यह हमारे सूबे बिहार का उदाहरण है और मुजफ्फरपुर शहर का उदाहरण है। मुजफ्फरपुर के बिहार स्टेट सेन्ट्रल बैंक एम्पप्लाइज यूनियन के प्रेसीडेंट ने भारत सरकार के श्रम मंत्री के पास एक तार भेजा है और उस तार की प्रति वित्त मंत्री के पास भेजी गई है और हमारे कम्युनिस्ट दल के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त के पास उस की कापी भेजी गई है। मेरे पास भी भेजी गई है और अन्य कई संसद सदस्यों के पास उस की प्रतिलिपि भेजी गई है। मैं उस को इसलिए यहां सुना देना चाहता हूं ताकि आप को नोटिस में यह आ जाए कि आर के अधिकारी मामूली-मामूली बात के लिए किस तरह से कर्मचारियों के साथ पेश आते हैं। वह तार इस प्रकार है :

"Mr. Davar Zonal Manager Central Bank Patna has ordered wage cut for our demonstration on 11th March last against Zonal Manager's unlawful whimsical antilabour works, apathy to institution and workers which invited demonstration stop. So Zonal Manager was fully responsible not the workers stop. He although bears antilabour attitude causing disturbance in industrial peace stop. He trampled workers with shoes during sitdown strike favouring nationalisation on 8th February, 1968 and apathy to advances to poor and neglected sectors leaves no doubt about his antinationalisation attitude stop Squandering of public money by ill motivated bad advances about 67 lakhs with packrukhi sugar mill amount exceeding even face value caused resentment amongst workers stop Umbrella to corrupt officers has allowed rampant corruption stop Necessary enquiray and Action solicited or serious breach of peace apprehended."

यह तार है जो कि भेजा गया है। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को आप को देखना चाहिए और कम से कम ऐसे लोग इस बैंकिंग सेवा आयोग में न रखे जाएं और न ऐसे लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंक में रहने का अधिकार है। इस लिए आप की नीति के प्रति जिन में आस्था हो, ऐसे ही लोगों को आप इस में रखिये।

दूसरी बात अनुसूचित जाति और जन जातियों के बारे में कहना चाहता हूं। उन को सुरक्षा देने की बात कही जाती है और नियुक्तियों में उन के लिए विशेषाधिकार दिये गये हैं लेकिन इस सिलसिले में मैं एक ही उदाहरण और देना चाहता हूं। आप के यहां कानून ठीक है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। इस चीज को भी देखा जाना चाहिए और यह जो इस तरह का कमीशन बन रहा है या जो आप के दूसरे अफ़सरान हैं उन का यह कर्तव्य है कि वह देखें कि आप ने जो नीति बनाई है, उस का पालन होत

है या नहीं। पटना के रिजर्व बैंक में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के 100 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उन का प्रोमोशन नहीं हो रहा है। मैंने पिछले सत्र में भी यह सवाल उठाया था और वित्त मंत्री जी की तरफ से मुझे यह जवाब दिया गया था कि आल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्प-लाइज एसोसिएशन से शायद कोई उन का समझौता हुआ है, जिस समझौते के कारण कठिनाई हो रही है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं जबतक कि एसोसियेशन के लोगों से पुन बात न हो जाए। जब यह बात शेड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों को मालूम हुई, तो उन्होंने आल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन को एक चिट्ठी लिखी और उस के जवाब में आल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन के सचिव ने जवाब दिया, जिस की कापी अभी मेरे पास नहीं है और अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन के पास उस को भिजवा दूंगा, कि हमारा ऐसा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है कि आप लोगों को प्रोमोशन या दूसरे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो ये आफिसर किस तरह से जवाब देते हैं? ये इस लोक सभा का बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के प्रसंग में यही निवेदन करूंगा कि आप इस बात की जांच करवाइए कि यह बात कहां तक सही है। अगर इस में कोई गलती है तो उस को सुधारा जाए और शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के जो 100 से ज्यादा लोग हैं उन को प्रोमोशन देना चाहिए और उन को दूसरे अधिकार मिलने चाहिए।

अध्यक्ष जी अभी कई सदस्यों ने कहा कि जातिवाद के आधार पर बहाली होती है, तो मैं भी यह कहना चाहता हूं कि बिहार में बहाली में पैसे ले लिये जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जो सर्विस कमीशन आप बना रहे हैं उस के बाद ये बातें रुकेंगी और योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। जो आप का क्राइटीरिया है या मापदंड है, उस के आधार पर भर्ती का काम चलना चाहिए और जातिवाद के नाम पर अयोग्य आदमियों को न रखा जाए और पैरवी के नाम पर जो नियुक्तियां होती हैं या अफसरों के लोगों को नियुक्त कर लिया जाता है, वे नहीं होना चाहिए।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के बैंकों में बहुत से अस्थायी लोग भर्ती हैं। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को निकाल कर फेंक नहीं देना चाहिए। ऐसा न हो कि जब यह कमीशन बैठे तो ऐसे तमाम लोगों को रफूचक्कर कर दें और कह दें कि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि टैम्पोरेरी तरीके से जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, उन को भी रखा जाए।

यह बहुत आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों के सदस्यों को उन इलाकों की भाषायें जाननी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई हिन्दी इलाका है, और वहां के आयोग का कोई सदस्य हिन्दी भाषा ही नहीं जानता है और अंग्रेजी में बात करता है, या किसी गैर हिन्दी इलाके में आयोग का कोई सदस्य केवल हिन्दी ही जानने वाला हो। इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्रीय आयोगों में विभिन्न भाषायें, और खास तौर से उन क्षेत्रों की भाषायें, जानने वाले लोग रहें।

क्लास फोर के बहुत से एम्पलाईज मैट्रीकुलेट होते हैं। अब तो कई बी० ए० पास व्यक्ति भी चपरासी का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ऊपर की नियुक्तियां और प्रोमोशन का रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि वे बरसों से बैंकों की सेवा करते रहे हैं।

[श्री रामावतार शास्त्री]

बैंकों की नियुक्तियों में जहां जात-पात का विचार नहीं होना चाहिए, वहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईसाई आदि का भेद भी नहीं करना चाहिए । कमीशन को यह समझना चाहिए कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, सब धर्मों के लोग भाई-भाई हैं और एक भारत माता की सन्तान हैं । इस लिए कर्मचारियों की नियुक्ति में इस प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए ।

इस समय बैंक उद्योग में आल-इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन एक मात्र प्रतिनिधि-मूलक संगठन, या कर्मचारियों के विशाल बहुमत का प्रतिनिधि संगठन है । मैं यह बात जानता हूं क्योंकि बैंक कर्मचारियों के संगठनों से मेरा भी कुछ सम्बन्ध रहा है । सरकार को उन लोगो का सहयोग जरूर लेना चाहिए । इस समय बैंकों में जो गड़बड़ियां और त्रुटियां हैं—काम में ढिलाई हो जाती है, समय पर काम न होने के कारण जनता असंतुष्ट और नाराज होती है और बैंकों में भ्रष्टाचार भी घुसने लगा है—, सरकार उन को कैसे दूर करेगी ? ये त्रुटियां केवल सरकारी डंडे से दूर होने वाली नहीं हैं । ये केवल इमर्जेंसी से दूर होने वाली नहीं हैं । यह ठीक है कि इमर्जेंसी का असर जरूर पड़ा है, लेकिन आल-इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन आदि जो बैंक कर्मचारियो के प्रतिनिधि-मूलक संगठन हैं, उन का सहयोग लेना जरूरी है ।

आल-इंडिया बैंक इम्लाईज एसोसियेशन इस दिशा में काम भी कर रही है । क्रेडिट पालिसी में जो गडबडी और कमी है, जिस की वजह से इजारेदारों को ज्यादा कर्जा मिल रहा है, उस नीति को बदलने के लिए आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन सरकार से बहस मुबाहसा कर रही है, सरकार पर दबाव डाल रही है । कर्मचारियों में जो ढिलाई आ गई है, बैंकों में जो भ्रष्टाचार घुसने की कोशश कर रहा है, उस के खिलाफ भी यह संगठन चुस्ती के साथ काम कर रहा है, और आगे भी करता रहेगा । इस लिए सरकार को उस का सहयोग जरूर लेना चाहिए ।

बैंक बड़े महत्वपूर्ण संगठन हैं । आम जनता और किसानों तथा गरीबों के साथ उन का सम्बन्ध है । मुझे विश्वास है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर आयोग ने काम किया और उस के मुताबिक कर्मचारियों की भर्ती हुई, तो हम अपने देश में राष्ट्र-विरोधी शक्तियों, फाशिस्ट शक्तियों और जनतंत्र विरोधी शक्तियों को कमजोर कर सकेंगे और चाहे वे लोग आनन्द मार्ग में हो, या आर० एस० एस० या जमाअते इस्लामी में हो, हमे उन को निकाल बाहर करने मे आसानी होगी ।

अध्यक्ष महोदय यह बिल बड़ा स्पेसिफिक है । मैं समझता था कि आप इस पर भी आयेंगे । आप ने तो इस को जेनेरल डीबेट बना दिया है ।

श्री रामावतार शास्त्री मैं तो बिल पर ही बोला हूं । कमीशन कैसे बहाल हो, उस का क्या रूप हो, इस बारे में मैंने सारी बाते कही हैं । मैंने बैंक एम्पलाईज से सहयोग लेने की बात कही है, क्योंकि आज के जमाने मे वह बहुत जरूरी है । विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कहना मैं भूल गया, क्योंकि उस का इस विधेयक से तालुक नही था ।

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay-North-East): I welcome this Bill. The proposed appointment of the Banking Service Commission is no

doubt a welcome step but at the same time it should be realised that the Bill has a very limited scope and, as you just now said, has a very specific purpose. It marks the beginning of the process of rationalising and of raising efficiency that the Government want to introduce in the banking service as a whole. From that point of veiw, people have got high expectations. Therefore, I am very much interested in seeing that even with this limited scope of the Bill, the step that is now being taken becomes an effective step and becomes a success.

We are told that this Bill has been taken from a model. It has come out of the recommendations of the Banking Commission and the model that has been suggested is the Union public Service Commission. I doubt very much whether we can take today the model of the Union Public Service Commission for the nationalised banks. I have nothing to say about the Union Public Service Commission, and besides here it is not the also. But if needs to be noted that the requirements, the purposes and the objectives that have to be fulfilled m respect of the services to be rendered by the banks and the role to be played by the banks in bringing about social and economic change are diffrent. The recruitment of the clerical and allied categories and junior officers is sought to be centralised now. Though the purpose is laudable, the way in which it has been drafted is not very conducive to the fulfilment of the objective. The important Clauses of the Bill are 4, 7, 10 and 12 as they laydown the composition of the Commission and its powers and functions. However, there is a big gap between the objective of regularising recruitment and providing good people to the banks. The objective is to take away these functions from the individual banks and vest them in the Commission, but it is not completely vested in the Commission. The employment policy and personal policy pursued by nationalised banks have not been covered in the Bill. In the matter of recruitment, the utmost that has been done is to provide for holding examinations for appointments. Examinations only decide the eligibility for selection and do not constitute employment in itself. Employment implies not only the selection processes but also the actual placement on the job. Placement of the right man at the right place is a very important function which has been deleted from the function of this Commission.

12.30 hrs.

[SHRI G. VISWANATHAN *in the chair*]

A statement is to be submitted by each bank during the remaining period of the first year and then as early as possible in the beginning of each subsequent year, regarding the vacancies available in various categories. The Commission will keep a record of these vacancies but it has no power to force them to make the placement It can only recommend and the banks are completely free to decide whether the vacancies are to be filled or not. There is no time limit fixed within which the vacancies have to be filled. We do not want to have frustration among the educated young people of this country. Therefore, let there be some kind of an advisory committee in which the representatives of the unions and the representatives of the management can lay down jointly the employment policy which includes not only the selection of persons and the rules for the selection of persons but also the new employment potential. These rules should be applied for regulating the management's right on reorganisation of the Department which touches the employment schedule also. So, these things are necessary. Further, not only the reorganisation policy of the Management, but even transfers, promotions are to be considered. They are also part and parcel of the employment policy. Unless you touch and regulate the promotion policy of the bank Management, and if transfer policy, how are you going to fill up posts? And your recommendations will also have no meaning.

[Shri Raja Kulkarni]

Suppose the Central Bank of India in Bombay, communicates that there is a vacancy in its Calcutta office. They are transferring a man from Bombay office to Calcutta office. Are you going to create a conflict? What are the rules? I want to know whether a man recommended by the Calcutta Regional Office of the Commission should be employed by the Central Bank or a person should be transferred by the Central Bank from Bombay office to Calcutta office? What are the priorities to be laid down for transferring a person from one place to another, from one region to another and from one location to another ? These are the policies which should be laid down jointly by the employees and the Management There should be some guidelines for the Commission They should reguarly be in touch with the Management and the Management must follow these guidelines. Unless the Commission has got this kind of powers and functions, merely holding examinations and preparing lists of eligible candidates will not be very effective in bringing efficiency in the cadre of the banks

We have been seeing that the UPSC has been there for a very long time They are holding examinations for Railways, for Posts & Telegraphs and for other Departments. Yet we are not in a position to say that it has caused efficiency. Something else then is required We would, therefore, like the Minister to assure us about all these functions which are necessary There are complementary and auxiliary in nature to make the main function of the recruitment a success

In the objectives of the Bill, it is stated that so far as the fresh recruitment in the Jr. Officers, Cadre is concerned, it shall not be less than 25 per cent. Now, there are agreements in some banks. In seome of the agreements, it is stated that the fresh recruitment in the Junior Officers' Cadre can only be upto 15 per cent. Now, what will you say about the existing agreements? Are these to be set aside ? You are going to tell the Management to recruit fresh candidates in the Jr. Officer Cadre when the agreement provides that it cannot be more than 15 per cent. So, there ought to be categorical assurances from the Minister on the Floor of this House that in the existing agreements with the unions of the banks, if there are a specific provisions in respect of promotion, recruitment and transfer, these will be protected under this legislation, so that they can implement those provisions effectively and efficiency can be increased. If this is not done, then it would be very difficult to make this effective.

Many of these managements have got separate training colleges and schools. If the Banking Commission is going to hold examinations, it is also necessary that this Commission takes over the functions of coordination and centralisation of the training institutions which are existing with these 14 nationalised banks. It is then and then alone that they will be able to provide a good cadre to the banks.

With these observations, I support the Bill.

SHRI SHYAM SUNDAR MOHAPATRA (Balasore) Mr. Chairman, Sir just as the people of Great Britain, the Magna Carta was the beginning of popular representation to bank nationalisation was the beginning of all positive and radical measures in our country.

I am reading out from page 2 of the Bill regarding the Chairman and members of the Commission. It says:

"The Chairman and members shall be persons who, in the opinion of the Central Government, are men of ability, integrity and standing and have special knowledge of, or practical experience in,

financal, economic or business administration or in the administration of Government or any other matter which would render such person suitable for appointment as Chairman or memer."

What I want to emphasise is this. In a radical economy or in a society which is having radical transformation from feudalism to socialism what is essential for the selection of a Chairman is the commitment of a person in terms of integrity commitment in terms of honesty and commitment in terms of representing the general will of the people. Unless the Government is going to translate this attitude into action, all these things will sound only hyperbolic.

Mr. Chairman, all these IAS officers today enjoy a certain amount of independence, they try to feel that they are probably a separate class of people, a separate species altogether to guide the decisions of the Government. Similarly, if these people, bank executives, go to feel that they are all big bosses (*bara sahib*) in the national economy, then the entire purpose will be lost. So, I would urge upon the hon. Minister certain salient points in selecting an executive, the first criterion of selection of the Chairman and members of the Commission should be the commitment of the Chairman and the members to the purpose for which they have been selected. Unless this is done, we cannot have the right type of persons. If the Chairman does not feel one with the popular impulse, one with the general will, one with the general reaction in the country to the Government policy, the entire recruitment will be based on fallacious assumption. Here it is written that the term of the Chairman will be five years and he will be there until he attains the age of 65. Well, there is nothing wrong in it. He may be there for five years or seven years. But why do you fix the age of 65? Why not have young people,? Why do we lose sight of the fact? Mr. Chairman, you are a young man. You represent the younger generation. Do you feel, therefore, Mr. Chairman, that a man of 60 or 65 will feel the same thing as I feel? There will be a generation gap. So, I think the age limit should be fixed upto 60. When we are retiring our people at 58, why cannot we fix the maximum age limit at 60?

We know that there will be different classes of people who will be recruited. There will be Clerks, Junior Executive and Senior Executives. The total number of bank employees has increased three-fold during the last 15 years. By the end of June 1971, there were two lakh banks employees spread over 2,000 branches. The Adarkar Committee estimated in 1968 that there were 20,000 officers and 1.32 lakh Clerks.

So, in the fitness of things there should be a Bank Service Commission. In my speech in Lok Sabha in 1972, I had suggested that there should be a Service Commission like the Railways Service Commission or as we recruit our IAS and allied officers. Unless this is done, the banks will have the independence to recruit persons as they like, as they choose and as they determine. There would not be any guidelines or a specific policy.

Mr. Chairman, the number is increasing day by day. Probably, every year, we are recruiting 47,000 people in the banks. About 18 per cent of them are officers; 24 per cent of them are subordinate officers and 58 per cent of them are clerks. What will be the number of these people? According to Mr S. D. Varde, there will be 3.38 lakh people by 1975, 4.97 lakh people by 1980 and 7.30 lakh people in 1985. It is a monstrous number. Unless the Service Commission is geared up to the extent that they should determine the right type of people, the very purpose for

[Shri Shyam Sunder Mahapatra]

which the 14 banks were nationalised will be lost.

While speaking on this Bill, I would like to suggest another thing to the Government which, probably, another hon. Member has also suggested. That is very important. These executives must know the local language. When we send IAS and IPS officers to different States, the first emphasis laid is that within two years they must learn the local language upto the middle standard. We must emphasize that these people must also learn the local language. I have seen it with my own eyes and I have once represented to our dynamic hon. Deputy Minister that these Bank Managers do not behave properly with the rural people. They take them as cats and dogs, not even as Tom, Dick and Harry. There behaviour is very bad, absolutely beyond imagination. Why? Because they hold in their hands the power of money. So, the poor people coming from villages for credit are turned out by clerks. They do not understand the local language. So, the first thing that we must emphasize is that they must learn the local language.

The Banking Commission had stated in their voluminous report about recruitment that "to be effective, the recruitment should be attempted to attract appropriate talent in terms of skill and attitude." The Banking Commission in their wisdom had suggested that, while selecting people, we must select them in terms of skill and attitude. By "attitude", I mean "commitment". They should be committed to the social transformation, committed to the socialist objectives and committed to the need of the time. Unless it is done, I think, we will lose sight of the basic fact.

Now, there will be socialists also in this category of officers. There will be economists also, there will be statisticians and legal experts also. Again, while selecting these people, we should not lose sight of the fact that we need certain type of specialists; certain type of economists. There are economists who believe in laissez-faire; there are economists who believe in Marxist economy; there are persons who believe in Gandhian economy. The present Government is committed to a definite type of economic transformation. While selecting these people, we must bear this in mind that we need particular type of specialists, particular type of economists, to lay down the policies of our banking operations.

Today, what we see is that there is a fall in deposits in the banks. There is a disparity between the bank activity in the rural areas and in the urban areas. Every bank wants to open branches in the urban areas. They do not feel that they should devote more energy in elevating the standard of the rural people. They should have a comprehensive plan to establish rural banks. What do we mean by a rural bank? As the Banking Commission had said, it means, "A primary rural bank is to serve a rural population of 5000 to 20,000" Wherever there is a large village, wherever there is a population of 20,000, to give credit facilities to these people, a rural bank should be established As you know, 80 per cent of people in our country live in villages. The vulnerable section of people, the tribals, the Harijans, the backward people the Muslims, come from villages rural areas. Unless we try to improve their standard of living, unless they feel that bank nationalisation has been a success, unless they feel that nationalisation of 14 scheduled banks is the Magna Carta of India's social transformation, everything would seem to be a hyperbole and we will feel that we have done nothing.

With these words. I support this Bill. While doing that, I must mention one thing more and that is that

there are banks other than these nationalised banks. What about the recruitment policy of those banks? The Banking Commission had stated, "If any Commercial Bank in private sector also desires to make use of the services of the Commission, it should be able to do so on mutually agreed terms." It is also there in the Bill. Why wait for a request from the private banks? Why not make it compulsory that those banks also when they want to make recruitment must go through Banking Service Commission. The banks which have not been nationalised also serve the people. I would urge the Minister to think over this proposal that the other banks also while making recruitment should take the service of the Banking Service Commission.

Mr Chairman, Sir, I think, I have put my points very squarely here and the hon. Dy. Minister while replying must also try to answer one or two points

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I am grateful to you for giving me time to speak. I would not have spoken on this Bill; I had no mind to speak, but some of the utterances or a portion of the speech of Mr Stephen has really provoked me to speak I am sorry, my hon friend, Shri Stephen is not here now.

During the course of his speech, while bringing to the notice of the hon. Minister certain mal-practices of the banks, Shri Stephen said that there was a collusion between the bank management and the bank employees. I do not know how he got this impression of collusion. If there is any understanding between the employees and the management in the nationalised banks, that should be hailed by this House and I must appeal to my hon friend Mr. Stephen to kindly consider one point very seriously. The All India Bank Employees Association is the most powerful organization and today, Sir, when we are talking of 14 banks being nationalised, let us remember those employees and pay them proper compliments for raising the slogan of nationalisation since the very inception of the All India Bank Employees Association. I know, day in and day out, whether in the offices or in the streets, whether in the towns or in the rural areas, every bank employee under the banner of the All-India Bank Employees Association was shouting everyday practically that the banks should be nationalised. We called these banks a sort of *Alladin* lamp in the hands of the capitalists and monopolists. We were insisting all the time that you shou'd take away these banks from their hands because this was the *Alladin* lamp by which they could create anything they wanted. Instead of congratulating the bank employees, he says that there is a collusion between the management and the bank employees and what is the collusion for? For exploiting the peasants and for exploiting the farmers. I do not know, if Mr. Stephen is suffering from some obsession of corruption. I can vouch for the organization which I represent, the All-India Bank Employees Association which is the strongest. It has been proved even by verification that their leaders Shri Parbhatkar and the late lamented Shri Parwana never colluded with the management; they fought with the management, but on the other hand, the union affiliated to INTUC which is headed by Shri Stephen tried to break the strike Whether that was the collusion or this was the collusion, I do not know. I can assure you once again and assure my hon. sister, I should say, of the support of the All India Bank Employees Association. After the emergency when the meeting was called recently by the Labour Minister, Shri Dange, who represented All India Trade Union Congress and Shri Parbhatkar who represented the all-India Bank Employees Association, voluntarily decided to cut 50 per cent of the overtime. Was it not an act of

[Shri S. M. Banerjee]

patriotism? Was it not an act of nationalism? Do you call them colluding? I should say that we should not condemn those who cannot possibly defend themselves. I do not say that all employees are honest and I do not say that all M.Ps are honest. How can I vouch for everyone? There is dishonesty everywhere and in every facet of our life. Those employees who are corrupt should be punished. By all means, do it. I can understand if some employees are in collusion with the management which affects ordinary people which affects even businessmen or peasants or any kind of people. Then they must be brought to book but let us not condemn everyone of them.

Then, again, he said that the Labour Minister is in the know of the leader who wanted a bipartite committee. He said that if a bipartite committee was demanded, then he would scuttle all the tripartite committees. I do not know what he meant by it. Is he aware that the apex body of the banking industry is a bi-partite body and the Labour Minister is just an associate member? We have been demanding that there should be bipartite agreement, bipartite negotiations, bipartite settlement and a bipartite committee to settle all the outstanding problems. Why should I ask the government to intervene every time? We do not want the government to intervene. Supposing there are two wings, the management and the employees and they sit together presided over by the Finance Minister or the Deputy Minister and if they can possibly settle all the issues, why should there be any tripartite body? We have always demanded bipartite committees. That Mr. Stephen should know and he should ask Mr. Bhagwati who is the Chairman of INTUC whether the apex body of the banking industry in a bipartite body. Knowing that, why should he threaten the poor Deputy Labour Minister? I do not know what is in the mind of the Member. We have demanded a bipartite body in every industry whether it is textile or whether it is the sugar industry or any industry and only where the employees and the management could not come to a settlement, we want the Labour Minister or the government to come and help us.

About direct recruitment, it has been raised to 33 per cent from 25 per cent. I want young and energetic people to come in. I have nothing against the younger generation. I want them to come up. In this case if the percentage is increased, what happens to the existing employees? Stagnancy. Stagnancy of 5 years or 6 years or 10 years in a particular bank. The net result will be that they will lose all incentive. Everywhere we are asking that there should not be any stagnancy for more than 5 or 6 or 10 years. Otherwise, they will lose incentive. I would request whether this 25 per cent should not be kept as it is and not raised to 33 per cent. If it is a question of more employment, let more banks be opened. Have a bank for every village and if not for every village, have one for every five villages combined and if you do that, I am sure the banking industry will prosper.

I would request the hon. Minister to kindly consider this point whether the same rules should not apply to those banks which have not been nationalised I would mention the foreign banks. Take the Grindlays Bank. What is happening there? During Pakistan's aggression, they published a map in which Kashmir was shown as a disputed territory It was not necessary for the Grindlay Bank to do that I do not know whom they wanted to please. They published a map in which Kashmir was shown as a disputed territory. This helped Pakistan. They quoted it too I would request the hon. Minister to kindly see that these rules are made

applicable to those banks too—commercial or otherwise.

13 hrs.

All India Banks Association recently gave an assurance that they will serve the people to the best of their ability. If there is a complaint against anyone that can definitely be looked into. We can definitely distinguish between a worker and a shirker. Worker is a worker, shirker is a shirker. Shirker is a liability both on the union as also on the country.

I once again request my hon. friend Shri Stephen to kindly read my point and let the hon. Deputy Labour Minister not be threatened. He is shivering every time. We stand for a bipartite body and not for a tripartite body.

With these words, I conclude.

SHRI P. K. GHOSH (Ranchi): I welcome this Bill since this will eliminate nepotism, favouritism and corruption in the matter of employment to a great extent. This will also enable us to select the right type of personnel for clerical and executive level.

While welcoming the Bill I would like to make one or two suggestions. I want that Clause 3(4) should be amended. This clause says:

> "The Commission shall have regional offices in such State or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government."

I would suggest that the regional offices should be established in every State. I want to stress this because it has been our experience that wherever the regional offices are located, the people of that particular State can take the advantage in the matter of employment. The people of the other neighbouring States are mostly deprived of employment as there are no such regional offices there. Therefore, there should be regional offices in every State so that local people of that particular State get priority in the matter of employment in that particular region.

Government of India has laid down a policy in regard to recruitment in all the public sector undertakings. Although banks had been nationalised five years back, yet banks are not following this policy. As per policy of the Government of India recruitment for the post carrying pay up to Rs. 500 p.m. should be made from out of the local people. But this is not being practised by the nationalised banks. There is a lot of favouritism and nepotism. Very few Scheduled Tribes people get employment there. While I say, there should be regional bank in every State, there should also be regional banks in the areas where there are Scheduled Tribes. The Scheduled Tribes do not want to go out of their homes. Therefore, in all the tribal areas there should be one regional bank so that the Scheduled Tribes get ample opportunity for getting employment in the banks

If you look to the figures of employment of Scheduled Tribes and Scheduled Castes as well as the members of the minority community you will find that their percentage is extremely low. Although in the Bill it has been provided that certain percentage of reservations will be kept for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would also suggest that in order to see that proper opportunities are given to scheduled castes and scheduled tribe people. the membership of the commission should also be given to one scheduled caste and one scheduled tribe person and also there should be a member of the minority community to protect the interests of the minority community, because, we find that

[Shri P. K. Ghosh]

in many cases the minority communities do not get the proper opportunities of employment in the banks.

There is a lot of other irregularities in the banks and the banks' functioning needs to be toned up properly. After the nationalisation of the banks, efficiency has gone down very much. The depositors are harassed and they have to wait for hours for clearing their cheques. If you want to clear some cheques through these banks, it takes months. I have experience about this. For collection of cheques by one bank from another bank which is situated seven miles away, it takes one month. This is the situation which prevails in the banks now-a-days. Normal courtesy is not shown to the depositors by these bank employees. After all it is because of the bank depositors that these bank employees get their salaries, but the depositors are being treated like beggars when they go to the banks. The functioning of the banks should, therefore, be properly toned up. It should be seen that the depositors are properly treated by the bank employees.

There is too much of corruption in the banks. When banks give loans, in some of the cases the loanee has to give some money for grant of the loan. I am told by some of the applicants that in some banks they charge 10,000 rupees for granting a loan for a bus or truck chassis. Another thing, Sir. For mini-buses, we have evolved a scheme that the unemployed diplomaholders and graduates will be given loans. But the banks insist on them to apply for a particular brand of mini-bus. Only then they will get the loan. The agent of a particular brand of mini-bus tells the applicant that he will get the loan sanctioned for him if he applies for this particular brand of mini-bus. He says 'I will ensure that the loan is granted by the bank'. It is said that the particular brand of mini-bus company pays Rs. 2,000 per mini bus to the bank management. There should be vigilance on the proper functioning of the banks. The small-scale industries and the small farmers are not getting the loans whereas big people are taking away most of these loans. Some of the executives are out to frustrate the whole purpose of nationalisation.

I suggest that in all branches of the banks there should be a 'Public Complaint Book' like the Railways. Whenever there is a complaint the public may be allowed to enter their complaints in the complaint book. The management should go into each and every complaint and take prompt action. We should not solely depend upon the bank management, for taking action against such complaints because the management may have sympathy or some softcorner for their employees. There should be a vigilance squad appointed by the Ministry of Finance to go in to the complaints about the banks and see to the complaint books and examine as to what action has been taken by the bank management against such complaints and, if they are satisfied that the bank management has not taken sufficient and requisite steps to mitigate such complaints or has not taken proper care to remove the grievances of the public, then the vigilance squad should recommend to Government for taking suitable action against the management of the bank And only if this is done, we can expect that the banks will function properly.

With these words, I support this Bill.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Banking Service Commission Bill, 1974. In fact, I am one who has always been pleading for the creation of Public Sector Service Commission. Experience has shown that there were

divergent and conflicting service conditions with regard to recruitment, promotion and dismissal in various public sector undertakings, instead of being uniform. What is more important in these public sectors is the well known maxim "not who knows what but who knows whom". In some of the Heavy Engineering concerns in public sectors, I found that one used to be promoted as Executive Engineer after three or four years of service, whereas in others, there were engineers who even after ten years were still rotting as Assistant Engineers, that is, in Bokaro Steel Ltd., N.C.D.C., H.S.L., or MECON and H.E.C. The same is true of the banking services also As a member of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we have found that sons and relations of bank employees were enjoying more protection and getting greater weightage than even the members of the scheduled castes and scheduled tribes. Favouritism, nepotism and corruption, if I may say so, are rampant in some form or other in certain levels in all the banks. Therefore, the creation of the Banking Service Commission is a welcome move and in the right direction provided the direction is known. I hope that the ills that are prevalent in banking services will be rooted out and we will carry forward the onerous responsibility of bringing about a social change, and the purpose for which the fourteen banks were nationalised, will be served.

In this connection, I would like to sound a note of warning that the Members of the Commission including the Chairman should be properly selected and not by political consideration. They should be persons of high integrity, efficiency and drive and should be fully conscious of the policies and programmes of the Government. In this, as in many others, men of character are more important than money, machine and material. In the present context, the choice the personnel of Banking Service Commission carries an extraordinary and important burden. Let there be no mistake in this. If this aspect is lost, I am afraid that everything will end in a fiasco. I am reminded of a Hindi saying which says:

हरामी करने पर किसी को नमक हराम तो कह लेते थे

लेकिन नमक ही हराम हो जाये तो किससे शिकवा करे ।

That means if we want to cure the ills that prevail in the society, or say, in the body of a person, a suitable medicine is required. But, if the medicine itself is poisonous, then it will eat up the entire body. It must be clearly borne in mind that public servants are the greatest instruments of social change.

Here, I would like to invite the attention of the hon. Minister to Page 2 of the Bill, Clause 4(2). It says:

> "The Chairman and members shall be persons who, in the opinion of the Central Government, are men of ability, integrity and standing and have special knowledge of, or practical experience in, financial, economic or business administration or in the administration of Government or any other matter which would render such person suitable for appointment as Chairman or member."

Here, I would like to say that I do not think that there is even the remotest possibility...

SHRI S. M. BANERJEE: What is that book?

SHRI KARTIK ORAON: This is in the Bill. This is an indirect way of excluding the members of scheduled castes and scheduled tribes. By no stretch of imagination, a member of

[Shri Kartik Oraon]

scheduled caste or scheduled tribe will ever become a member. The question of his becoming the Chairman does not arise. Therefore, I suggest that persons for the appointment of the Chairman and members of the Banking Service Commission, apart from their being men of ability, integrity and standing, etc., it should be specifically mentioned that they must also have zest for the upliftment of the weaker sections of the society. Only then, will they be able to select persons of the right type for the other categories, in the lower levels, like the clerical and allied cadres, the junior officers cadre, minorities and other categories in the banking service. It may be argued that this would be taken care of. Government will always say that it will be taken care of, but. it is not possible to know the working of the mind of a man. It has been well established that men do not possess the facilities for investigating the working of a man's mind, and were uncertain as to the possibility of assessing it accurately. It is common knowledge that intentions of man cannot be probed for even the devil does not know men's intentions.

I would, therefore, like to suggest that Clause 4(2) should provide for inclusion of one member each from scheduled caste, scheduled tribe and minorities in the banking service commission and also in all regional offices. Either, they should be accommodated within the eight members of the Commission or number should be raised to ten or eleven. I think this point has been touched by the other members also. I am greateful to Shri Jamil-ur-Rahman who has advocted the cause of scheduled castes and scheduled tribes ably and rather forcefully. Only then, the cause of the weaker sections of the society would be served. Even in the selection of members from scheduled castes and scheduled tribes, special care should be taken to select the right type of person. Merely taking a member of the scheduled caste and scheduled tribe is not enough. He should be conscious of his rights, responsibilities and obligations to the society to which he belongs. He should not be a deaf and dumb representative in the Commission.

Sir, in this Bill, of course, provision has been made that reservations should be made in favour of scheduled castes, scheduled Tribess and other categories of persons. But, I am sure, Sir, that this will not be operative unless Clause 4(2) is suitably amended to include one member each from the scheduled caste and scheduled tribe and minorities. Sir, I am aware of the lacunae. Provisions of this nature alone have not worked well in many cases I will cite a few instances to clarify the position.

Firstly, a member of scheduled tribe was selected for appointment in the LIC in a reasonably higher position at Trivandrum. But, he was not allowed to join as the authorities were planning to circumvent his appointment by filling up the post by a person from other division. Secondly, during the visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled tribes to Bombay, it was pointed out that a person was wrongfully selected as a scheduled tribe for a Class I post in the Post and Telegraphs Department. It was investigated and later on it was found correct. But, the very top official who was at the helm of affairs ruled that we must not be so harsh as to remove him from service. One may show mercy, but, one must not be allowed to sell mercy.

Another case is one in which the UPSC had recommended two girls for IAS from Bihar as members of scheduled tribes when in fact they were not members of the scheduled tribes.

It is, therefore, that I suggest that the Commission should not only be a

rubber-stamp to go merely by records but should also exercise all reasonable care to see that wrong entry does not go unchecked. Only a member of the scheduled castes and of scheduled tribes will be able to help the Commission in this respect. It is, therefore, of paramount importance that the Commission should bave provision for the inclusion of a Scheduled Caste and a Scheduled Tribe to oversee that the reservation quotas for scheduled castes and scheduled tribes are resolutely filled up and the policies properly implemented in the scheduled banks.

I would like to invite your kind attention to the provision of regional offices. Bank nationalisation came as a clarion call to the nation to lift up the face of the teeming millions of the poorer sections. But bank nationalisation, so far as the scheduled tribes are concerned, has not been able to deliver the goods. I would, therefore, suggest that regional offices are located in tribal belts all over the country. Let the scheduled castes and scheduled tribes be associated with the policy-making body and not merely serve as dumb, riven cattle. Let the Commission be within the reach of the tribal people where invariably in all cases gigantic projects are located, not because of any favour or special consideration to the tribals but because the raw materials and infra-structure are available.

If you wish, hon. Deputy Minister—I hope you do—that the benefit should flow to the weaker sections of the people, my suggestions may kindly be accepted. If not, the creation of this Commission, or for that matter any other Commission, will run counter to the accepted policy of the Government.

Finally, therefore, I appeal to the Government to lay the foundation of this Commission on a sound footing. The Commission, if I may say so, should expressly and impliedly, directly and indirectly, serve as a prime mover in the implementation of the 20-point economic programme of our dynamic Prime Minister. It should not be a thing of beauty to look at but should be a thing of beauty to serve as a model and a source of inspiration to other Service Commissions existing in our country.

With these words, I support the Bill and wish the Bill and the Deputy Minister of Finance the best of luck.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINSTRY OF FNANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Thank you. I need it.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar) At the outset, I congratulate the Minister and thank her for bringing forward this Bill. When I read the statement of objects and reasons, I felt encouraged to speak on this subject, though I did not think at all of speaking in the beginning.

You know Parliament has constituted a Committee which is known as a watch-dog Committee and a high-power Committee. There we examined all the banks in India and also all the public undertakings in India. From my experience as Chairman of that Committee I am reminded of what happened when we first examined Air India. The Chairman of Air India happened to be an ex-military officer at the highest level. In the beginning, he talked with a certain air as if to ask why Parliament has taken up such a subect, it will deteriorate the standard of this water-tight compartment, Air India. Like that he went on. I allowed him to speak for about half an hour. After that, I put my first question. 'Please remember whom you are serving, whether you are serving the British Government or the National Government.' I repeatedly told him feel yourself whether you have been serving under the British Government or under the National Government of India. "Of course, I am under the National Government," he

[Shri D. Basumatari]

replied. Then, in that case, are you to sermonise the Government of India? I asked him and then I scolded him and brought sense into him. Then there was the case of the Reserve Bank of India. When I first examined them, the Deputy Governor of the Reserve Bank was very reluctant about the reservation of the posts for Scheduled castes and Tribes. Whlie we read out the terms of our committee, he had to apologise. Many banks were opposed to the principal of reservation but after our examination they agreed in principle for the reservation of posts for SCST. But then they pleaded dearth of candidates. When they said so; I started going to them with the copy of the applications along with the counterfoil of receipts for payment of the prescribed fees of Rs. 5 or 2.50. I told them that so many graduate applicants were waiting outside and if I wanted I could call them to prove that there was no dearth of candidates. This is the kind of attitude that they have to this problem. In Bombay in one bank I asked them to call the clerk who receives the applications and showed him the copy of the applications that I had and asked someone to trace out the applications that were with the office; he traced them out and said that there were those applications. I find that SCST candidates with MA First class qualifications are refused appointment saying that they are not suitable. That is the dirty mentality, and the rigid mentality of those people which I term as mental reservation. When we found that there were no SCST candidates in the IAS and IPS, we insisted that the Government of India should set up pre-examination centres. One is now at Allahabad, the second in Madras, the third in Punjab, the fourth in Assam and the fifth is in Delhi itself. By the establishment of these centres, I find now that the performance of SCST candidates is better in the IAS and IPS examinations, than the Class I and II service examinations in the centre and in the States. There is no dearth of intelligent candidates among the SCST. But they do not have the facilities. They cannot send their children to the public schools or Kendriya Vidyalaya because in Kendriya Vidyalaya only the children of Central Government servants are admitted and how many SCSTs are there in the Central Government service?

How can the students belonging to SCST get best education in the slum areas? How can they get best tuitions from the best teachers who are working in the Kendriya Vidyalaya and in the Public Schools? How can you expect them to compete in the public examinations with those candidates who have got their education from the Public Schools?

13.30 hrs.

[SRRI VASANT SATHE *in the Chair*]

Sir, the difference is not seen in this house or in the high official ranks. Here we are getting on all right. We have asked all the Departments and the appointing authorities to conduct examinations separately for Scheduled Castes candidate and separately for Scheduled Tribes candidates before the examinations for the general candidates are conducted. If the examinations for the general candidates are conducted first and for the SC ST some time after you will find that the standard of the general candidates will be high. Candidates belonging to the SCST appearing for the competitive examinations will be of lesser inteligence and therefore such examinations should be conducted earlier than these conducted for the general candidates. Now, the whole of the appointing authorities have agreed to conduct examinations separately for SCST. I hope that the banking institutions will follow the same principle. Hon. Deputy Minister should see to it that necessary circular to this effect is issued to all the banking institutions. The Minister may kindly see to it that within a period of three years, quota

for SC ST candidates is completed in these institutions as time bound programme. Do you know where we stand? In the field of services the percentage of SC is 2.29 and the percentage of ST is 0.39. This is the plight of our community. But people say that they have done many things, a lot of things for the SC ST. Therefore, in the line of the policy adopted by the U.P.S.C. to conduct examinations separately for the SC ST, we have requested that banks should also have pre-examination centres to recruit SC ST candidates as in the case of IAS and IPS stated before. They have agreed to do so and they are waiting for the orders to be issued by the Government. I request you kindly to see that the orders to this effect are issued at a very early date. Another suggestion I would like to make is that Clause 4(1) of the amending bill may be modified to include two persons from SC ST in the total number of eight members of the Commission. In the UPSC also there are two highly qualified Members, one belonging to SC and the other belonging to ST. They are Ph.Ds. Here also in your recruiting Commission I would request you to include one Scheduled Caste member and one Scheduled Tribe member. I may also point out that there is no dearth of SC ST persons to serve the Commission. Mrs. Rohatgi, I have examined all your banks and I have found that they are all lagging behind in the recruitment of SC/ST candidates. I request you to set a particular date, say two years or three years, and by that date the reservation obligations should be fulfilled by all the banks. There is no dearth of talents in our community, only the mental reservation should be removed.

With these words, I congratulate you for bringing forward this Bill and hope that our community will be taken care of by you.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, in the very beginning I would like to extend a word of thanks to the hon. Deputy Minister, through you, for bringing this long awaited measure.

Perhaps, you might be remembering Mr. Chairman, that in April, 1972 you and I were among 206 Members of Parliament who made a representation to the hon. Minister at that time, Shri Y. B. Chavan, for the appointment of a Parliamentary Committee to examine the recruitment policy of the banks and we were hoping that the mess which had been going on even after nationalisation, would be brought to an end. Three years is a long period and after three years 206 Members of Parliament have found that their voice has been heard. Anyhow, the appointment of this Commission will result in some healthy practice so far as recruitment is concerned. It would not be out of place to refer to the practice, the mess that had been prevailing in the past. I quote from the Report of the Banking Commission, page 350, para 14.9. It says:

> "Recruitment at Clerical Level—The recruitment policies followed by Indian banks in the past had hardly any scientific basis. In several cases minimum qualifications were not insisted upon and even non-matriculates were recruited for clerical posts. There was no proper evaluation of capacity and aptitude and often relationship, caste, community and recommendations played a big part in selecting persons."

Now, this speaks for itself, I would again refer to a document which is known as 'New Trends in Banking'. I think, this is the latest publication. When I come to recruitment in public sector banks I find these remarks:

> "When banks were in the private sector, they were naturally keep to restrict their recruitment to a particular group of candidates, sponsored by their friends, clients and employees, on the ostensible ground that trust is an important requirement in banking."

[Prof. Narain Chand Parashar]

These were the clients who were sheltered away even from the Parliamentary committees in the name of secrecy. And in the name of trust misdeeds were done on a large scale. Between 1969 and 1972 as many as 85,000 persons have been provided with employment in public sector banks without any competitive examination and without any common recruitment. An army of 85,000 persons had been mustered into the nationalised banks ostensibly to serve the nation on this very criteria which, I hope, is still continuing. I would request the Minister, through you, to find out as to what has been done to the existing people who were recruited on the basis of relationship, caste, community and recommendation and what is the answer to those young Graduates who have qualified but do not have the privilege of belong to the circle of relationship, caste, community which was demanded in these banks. This is a serious question. At least, they must be given some sensible training in human behaviour; and they must be shown that banking is a service-oriented programme. It is not a place for pleasure, where you can draw fat salaries and declare strikes at the slightest provocation, or even without provocation, even when you happen to be the highest-paid in the land. I would like to quota further; and also to say that these are the remarks which these people are supposed to have accepted while agreeing to sponsor the legislation for this Commission:

> "Whole accepting the recommendation for setting up of an independent common recruitment agency, it has been decided for administrative reasons and particularly in view of the large numbers involved in clerical recruitment that the common recruitment agency may, to begin with, confine itself only to recruitment of junior officers in the nationalised banks. The procedure for recruitment of clerical staff in banks is, however, kept under constant review...."

Which review? That review which suits them; not the one which suits the candidates, but those who manage the recruitment. It says further:

> "With a view to keep it not only absolutely fair and impertial..."

But now, something has to be done. What is the new slogan? It goes on:

> "but also to meet the employment aspirations...."

Here is the long-needed sentence, for which 206 MPs. were itching:

> "....of the people of the area where the bank offices are operating."

At last, the high wisdom has dawned on the high personnel of the banking department and the bank managers and directors and all these people, that the area where the bank is situated, should also be somehow linked to the bank, or to the branch. Mr. Chairman, this bill for the Service Commission, I am sorry to state, does not provide for even this hope that has been there, except that there is some vague reference in this documents to the employment exchanges. But what goes on the employment exchange is sheer mockery, because when you talk in terms of English, you forget the native language and the people of India, who hardly know what English language is. Not more than 5 per cent in India are conversant with English language. A majority of your clients and a majority of your borrowers are people who know only regional languages. I am sure, Mrs. Rohatgi, you would be giving a new gift to this country in this period of Emergency, if you announce that the examinations to be conducted for recruitment to banks will not insist upon the compulsory knowledge of

English; and further, that the knowledge of the local or regional language will be a 'Must'. Otherwise, you will ensure that no person is selected in Maharashtra who does not know Marathi; and no person is selected in Tamil Nadu who does not know Tamil. This is a very strange state of affairs in India that we go on thinking in terms of national development and all the time we are gravitating towards our own kith and kin either in the name of a universal language or in the name of efficiency or proficiency. God knows what. So, I suggest that the proposed test and the proposed rules for this test should take into consideration the fact that there are many schools in India to-day where the students do not know English, that they are coming only with the national language or any other languages. They may say that other languages are also national languages; I do not object; but they should not be debarred on this very score. Secondly, I want to support what Mr. Basumatari had said; because though I do not belong to that section of society, *viz.* the scheduled castes, I feel that when we make promises—and when in the Emergency we promulgate this 20-point economic programme, one of our most important programmes is that we shall take care of the weaker sections of the society; how do we take care of the weaker sections? We take care of them by not allowing a first class MA to be selected! That is the way our bureaucracy has been taking care of the weaker sections of the society. I want to ask the Minister whether this procedure will change or not. If it is not changed, then it will be a sad day for the country. Here I would very much recommend what the hon. Member Shri Basumatari has suggested. If you want to do justice to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you must have separate examinations for their recruitment. Otherwise, there is no hope of their getting fair representation. When you can recommend and create special training centres for recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the IAS, IPS and other civil services, how is it that you neglect them so far as banks are concerned. If you do not want the present position to continue, you must create training centres for the recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates for employment in banks on a crash programme basis.

The number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in employment in the various public sector banks has increased. But what has been the increase since 31st December 1970 when the figure was 47? According to this document the number has gone up to 116. In the case of clerks, 85,000 candidates have been recruited. The number of Scheduled Caste and Tribe candidates has gone up from 697 to 2,827. Is it fair representation? If 20 per cent of the people are from this section of the society, then for 85,000 their representation should come to 17,000. But, instead of 17,000 we have got 2,827 on 31st December 1972, according to this document, which is a Government of India publication. Therefore, the representation for the weaker section is woefully inadequate and something drastic, as suggested by Shri Basumatari, should be done so that thy can feel that they are given their due.

Shri Jarilurrahman raised a point when some people had some doubts in their minds. Clause 6 of the Bill says;

> "The Central Government may remove from office the Chairman or any member, who....
>
> (a) is adjudged an insolvent...."

He referred to the case of an officer, occupying the very high chair, who belongs to the Anand Marg. What prevent you from sacking that officer. Let Shri Jamilurrahman give the particulars and the House wants to know what action you have taken.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have requested him to give the particulars.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: When you are banning Ananda Marg and RSS, how is it that shelters are created either in the Ministry of Finance or in the Banking Department where these people can sit tight and finance these institutions from outside. We want firm action to taken against these people, if it is legally feasible. Anybody who is detected to have any leanings or connections with the banned organisations, if proof is available, should be debarred from becoming a member of the Commission and, if it comes to the notice of the Government after selection, he should be removed as soon as it comes to the notice of the Government. We are not afraid of anybody. If the Ananda Margis have selected 50 persons to be killed and if some of us are in those 50 persons, it is all right, but we will not allow them to have sheltered existence in the air-conditioned offices of the Secretariate or in the banks. You must be very strict here and you must mean business. We want to be sure that the people whom you are going to select are men of integrity, who are committed to the 20-point economic programme.

Then you say that half of the members of the Public Service Commission must be from the banking industry. If you want experts to be associated with the selection, you can have them as advisers. When we select lecturers or professors, we always have advisers. But if you insist that half of them must be from the banking industry, or from people who have experience of banking, it is trying our patience a bit too much. We cannot believe that those who have not been in the banking industry are not able to understand the mysteries or intricacies of banking. We cannot agree for a moment that the other four of the eight members who do not belong to the banking department are in any way inferior to those who belong to the banking department. This clause is highly unfair. If you are particular of having people who have special aptitude for banking, you can have them as advisers. They will give you their advice. Whenever in an agricultural university we have to recruit a professor, we always have as advisers people who are trained in the field of agriculture. But to insist that only those people can select fit candidates for the banks who have their connections with the banking department is not right, especially in the context of the state of affairs prevailing in the banks, as I have read out from the Banking Commission Report, which states that candidates have been selected on the basis of caste, community, relationship, kinship, friendship, recommendation and so on. So, what right have you to put forward this recommendation here in this Bill that at least four members of the Commission must be from the banking industry. This is not a desirable provision and the sooner it is removed the better it is.

Lastly, what have you provided for the ex-servicemen ? You have referred to the recuritment and reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But what about the ex-servicemen? Now they are included in "other categories". I wish they should also be mentioned in particular, like Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

One hon. Member suggested that the clause which provides for employment on compassionate grounds should be removed. I do not agree with that suggestion. If an employee of the banking department dies, a member of his family, his son or daughter, should be provided with employment on a priority basis on compassionate grounds. Here, an addition to "death". I would add "permanent disability", so that the family does not starve when he dies or is disabled. We may be angry or annoyed with an employee who is inefficient. But that annoyance should not be extended to his family in the case of his death.

Then, in the creation of regional offices, for heaven's sake please do not club the States. You consider it desirable that Manipur should be a full-fledged State which should have a High Court of its own and that Himachal Pradesh should have a High Court, a full-fledged Assembly and a Governor. Yet, you think that it does not deserve to have a regional office of the banks. Why is it so ? If you consider a particular area or particular region to be specially qualified to become a full-fledged State, to have a Governor, to have a University, to have a Public Service Commission and to have a full-fledged Assembly, what is the reason that it should not have a regional banking office? You must equate it with the other States so that the big States cannot dominate and so that the small States are not unrepresented by banks. I want to lay stress on the fact that every constituent State of the Indian union must have a region for itself in the banking structure. Whether their needs are big or small is immaterial; when they have their own Assemblies, High Courts and Public Service Commissions, they should have their regional banking offices.

Then, there must be a proper share of these posts for the local people. Otherwise if you create an all-India cadre for every post and make them transferable from one place to another there is scope for victimisation. The management can transfer one person from Kashmir to Kanyakumari. Or, if the bank manager or the Chairman happen to be from a particular State, he will select people from his own area and feel satisfied that he has done justice. The bank must be rooted in the soil; it must not float in the high seas. The recruitment policy should be so framed that preference will be given to the local people.

Then, there should be a report to the House every year about the recruitment that has been done, giving State-wise figures of employees in the bank, so that the people and their representatives know that people from their State are recruited in the bank and that the old practice or recruitment on the basis of kinship, caste, friendship, recommendation and relationship has been discarded once and for all.

With these words, I support the Bill.

श्री राम हेडाऊ (रामटेक) : सभापति महोदय, बैककारी सेवा आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बैंकों का व्यवसाय जो आज तक इस देश में रहा है, वह पूंजीपतियों के हाथ में रहा है। इतना ही नहीं आर्थिक क्षेत्र में जो वैस्टेड इन्टरेस्ट के लोग रहे हैं, उनके हाथ में यह धंधा रहा है और उसका परिणाम यह हुआ है कि पूरा संचालन उन्होंने आपस में बांट लिया, बराबर अपने अपने लोगों का उसमें नौकरी पर रखा, अधिकारियों के पद पर रखा और इतना ही नहीं, बैंकों में जो भी जमा होता था, उसका उपयोग भी निजी स्वार्थ के लिये किया। अब हमें उस परिस्थिति को बदलना है, इस दृष्टि से यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है—ऐसा मैं मानता हूं।

इसमें नियुक्तियों के मामले में जो आयोग बैंको के नियन्त्रण के लिये बनाया जा रहा है, इसमें कुछ सतर्कता का बर्ताव बहुत अपेक्षित है। क्यों ? हमने देखा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक हो या प्राइवेट सैक्टर में कोआपरेटिव बैंक हो, आज बैंकों के व्यवहारों में समानता का बर्ताव जनता से नहीं किया जा रहा है। इसमें दो वर्ग के लोग होते हैं। एक गरीब तबके के लोग जो आज तक बैंकों की ओर आकर्षित नहीं हुए, लेकिन जो दूसरे बड़े लोग थे, उन्होंने बैंकों से काफी फायदा उठाया, काफी पैसा उनको बैंकों से मिलता रहा। इसका कारण है—वहां का नौकरशाह उन्हीं के इशारों पर चलता था, उनको खुश रखने की कोशिश करता था और इसी दृष्टि से जाति, रिश्तेदारी के बलबूते पर वहां की नियुक्तियां हुई हैं।

[श्री राम हेडाऊ]

मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं—भण्डारा जिले में, जो महाराष्ट्र में आता है, वहां एक कोआपरेटिव सैन्ट्रल बक नामक संस्था है, जो कुछ महाभागियों ने 25–30 साल पहले स्थापित किया था। गांव के जो पूंजीपति लोग थे, वे ही उसके डायरैक्टर रहे, कुछ विशिष्ट जातियों के, वर्ग के लोग उसमें प्रमुख रहे और उन्होंने उस बैंक में जितने कर्मचारी भरे हैं, वे सब एक विशिष्ट जाति के थे। और उस बैंक का पूरा-पूरा लाभ आज तक वह उठाते रहे हैं। और आज भी यह स्थिति है कि वहां दूसरे लोगों को नौकरी पर नहीं लिया जाता है। उस बैंक की जिले में 18, 20 शाखायें हैं लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग उस बैंक में नहीं के बराबर हैं। जिन महानुभावों ने इस बैंक को खोला वह सदा लाभ उठाते रहे तथा नये नये बैंक खोलते रहे। अभी अर्बन कोआपरेटिव बैंक उन लोगों ने खोला, जिसमें नौकरी देने के लिये एक एक व्यक्ति से दो, दो हजार रु० लिये गये। उनके दलाल इस काम के लिये हर वक्त तैयार थे। इस प्रकार जिनके हाथ में बैंक की सत्ता रही है उन्होंने इस का दुरुपयोग किया है। यह बात नहीं होनी चाहिये। इस बिल से उम्मीद है कि इस बात को रोका जायगा।

14 hrs.

अब मैं भर्ती के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम देखते हैं कि बैंकों में भरती के लिये एम्प्लायमेंट एक्सचेज से नाम मंगाये जाते हैं। किन्तु वहां भी एम्प्लायमेंट अफसर किस मनोवृत्ति का है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि उसकी कारगुजारी को देखने का हमने अभी तक कोई यंत्र तैयार नहीं किया है कि वह सही ढंग से उचित और योग्य व्यक्तियों का नाम, जिस क्रम से नाम दर्ज किये गये हैं उसके अनुसार बराबर भेजता है कि नहीं। परिणाम यह होता है कि अगर वह अधिकारी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का जातिवाद को मानने वाला हुआ तो वह हेरफेर करके अपने आदमियों के नाम ही भेजता है, और जो बैंक के अधिकारी होते हैं उनसे उनकी तालमेल हो जाती है और वह बोलते हैं कि हमारे ही रिश्तेदारों के नाम भेजो, और वही लोग नौकरी में रख लिये जाते हैं। यह बात इसमें नहीं होनी चाहिये।

जो आयोग स्थापित हो रहा है यह रीजनल बैसिस पर भी होना चाहिये क्योंकि जो डायरेक्टर्स हम लेंगे नियुक्ति करने के लिये, जो आयोग में प्रमुख लोग लेंगे उनमें सामाजिक और राजकीय कार्यकर्ताओं का भी स्थान होना चाहिये। इसके साथ-साथ अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर आदि लोगों को भी, जो बैंकिंग के व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं, कुछ तबदीली लाने के लिये अच्छी सिफारिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। साथ ही आदिम जन-जाति के प्रतिनिधियों को भी इस कमीशन में स्थान मिलना चाहिये। और बैंक के अधिकारी तो रहेंगे ही। इस प्रकार से अगर इस आयोग को बनाया जायगा तो बैंक में कर्मचारियों की नियुक्ति करते वक्त जो अन्याय आज तक होता आया है उसको हम दूर कर सकेंगे।

वास्तव में नीचे के तबके के आदमी का उत्थान हमारे नये आर्थिक कार्यक्रम की बुनियाद है। बैंक की ओर गरीब आदमी आकृष्ट होना चाहिये। हम देखते हैं कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार आने वाले आदमियों के साथ समान नहीं होता। देहात से जो गरीब काश्तकार आता है उसके साथ जो व्यवहार होता है उससे कुछ अलग व्यवहार वहां के पूंजीपतियों के साथ होता है। पूंजीपति जब बैंक में जाता है तो उसको वहां बैठने को कुर्सी दी जाती है, लेकिन काश्तकार के साथ ठीक ढंग से बात

ली नहीं की जाती, बैठाने की बात तो दूर रही । पीछे से आने वाले का काम पहले होता है और छोटे आदमी की उपेक्षा की जाती है । यह बात नहीं होनी चाहिये । बैंक और उसके कर्मचारियों का सम्बन्ध सीधे जनता से होता है इसलिये उनको जनता के साथ कैसा बरताव करना चाहिये, समानता का व्यवहार कैसे करना चाहिये, इसकी ट्रेनिंग भी देना बहुत जरूरी है । इस बिल को लाने में सरकार ने जो दिलचस्पी दिखाई वह उचित ही है, हालांकि इसको और पहले ले जाना चाहिये था । फिर भी यह सही कदम सरकार ने उठाया है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर साढ़े तीन घंटे तक चर्चा की और हालांकि इस विधेयक का एक बड़ा सीमित दायरा था परन्तु उन्होंने बैंकिंग के सम्बन्ध में हर अंचल पर अपने सुझाव दिये हैं और टिप्पणी की है और जहां भी उन्होंने उचित समझा उनको अच्छी तरह से रगड़ा भी है । मैं खुश हूं कि इसी मौके पर कम से कम बैंक के सारे कार्य भार को अच्छी तरह से देखा गया और जहां कमी देखी गई उस पर प्रकाश डाला गया । मैं अपने साथियों का ध्यान जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस पहलू पर भी ले जाना चाहूंगी । राष्ट्रीयकरण के पहले क्या उद्देश्य हमारे सामने थे, किन मान्यताओं को लेकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कहां तक हम उस मंजिल तक पहुंचे हैं और क्या-क्या कमियां हैं, उनका निराकरण करने के लिये माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये उन की भी चर्चा की गई । इसमें दो राय नहीं हैं कि सारे देश के आर्थिक ढांचे में राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक बड़ा भारी कार्य-क्षेत्र है । हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो निजी क्षेत्र में बैंक हैं उनका राष्ट्रीकरण क्यों न किया जाय । सही है कि 80, 85 प्रतिशत बैंकों का काम राष्ट्रीयकृत है इसलिये जो उनका कार्य है वह जनता के सामने आता है, और उनकी सारी चीजें जनता के सामने आती हैं ।

जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय बैंक का नजरिया ही दूसरा था, उनका कार्य क्षेत्र दूसरा था, उनकी प्रणाली दूसरी थी, उनका ढांचा और मान्यताएं दूसरी थी । बैंक ग्रामीण इलाकों से दूर रहते थे क्योंकि उनका सम्बन्ध कामर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस से रहता था । इसलिये उनका नजरिया उसी तक सीमित था । आपने देखा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 8 हजार थीं जोकि 6 साल में बढ़ कर 18 हजार हो गई हैं । और खुशी की बात यह है कि करीब-करीब 50 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण अंचल में खोली गई हैं । ग्रामीण अंचल में उनका आगे बढ़ना, उनके दृष्टिकोण को बढ़ाना और व्यापक करना आवश्यक हो गया और इसीलिये उनकी शाखायें गांवों में खोली गईं । जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा किया गया । अभी हमारे पास बहुत से ऐसे ब्लाक्स हैं जहां शाखायें नहीं खुली हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-क्षेत्र यह भी है कि जहां-जहां ब्लाक हैं, जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें नहीं हैं, हम ने पांच-छः राज्यों का ऐनालिसिस करके देखा है कि बहुत से ब्लाक्स ऐसे हैं जहां तीन हजार से भी कम वहां की आबादी है । राष्ट्रीयकरण के समय औसत पापुलेशन प्रति बैंक 65,000 थी, जो 6 साल के बाद घट कर 30,000 प्रति बैंक औसत पापुलेशन हो गई है । फिर भी हम इसको और कम करना चाहते हैं । किसी-किसी जगह औसत इससे कम पड़ता है और कहीं कहीं इससे अधिक

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

भी पड़ता है। जहां हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां बैंकिंग की अधिक आवश्यकता है, जहां शाखायें कम खुली हैं वहां पर ज्यादा पदार्पण किया जाय यह हमारी इच्छा है। और इसी-लिये रोलिंग प्लान बनायी गई है जो तीन साल को ध्यान मे रख कर रैशनल स्ट्रक्चर तरीके पर परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है जिस से राज्यों में जो असमानता है, राज्य के अलग अलग अंचलों में जो असमानता है उसको दूर करके एक सामंजस्य लाया जा सके। यह सब होते हुए, मान्यवर, मुख्य चीज यह है कि केवल शाखा खोलने से तो काम नही होता, काम करने वाले ढांचा से काम नही होता है बल्कि अंदर की जो आत्मा है, जो आदमी हैं उनमें काम करने की निष्ठा होनी चाहिए, आदमियों के काम करने के विचार होने चाहिये, दृढ़ता होनी चाहिए और सब से ज्यादा क्षमता होनी चाहिए कि जो वह अपना कार्य कर रहा है उसको अच्छी तरह से वह कर सके। इसलिए जब से राष्ट्रीयकृत बैंक बने हैं, उनके लिए निरन्तर ट्रेनिंग का काम बढ़ता चला जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहती हूं कि हमारा ट्रेनिंग का कार्य क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि सारे ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के अपने अपने ट्रेनिंग के कार्य हैं, कुछ में कम है और कुछ में ज्यादा, मगर एक मशीनरी के रूप में, एक यंत्र के रूप में यह काम चल रहा है। मैंने शुरू में अपनी स्पीच में कहा था और जो आंकड़े हमारे पास हैं उन से यह सिद्ध हो जाता है कि हर साल हमारी ट्रेनिंग का कार्य बढ़ता चला जा रहा है और 1967 में राष्ट्रीयकरण से पहले जो एम्प्लाइज की ट्रेनिंग कराते थे, उनकी टोटल संख्या 1280 थी लेकिन जब से हमारी यह ट्रेनिंग शुरू हुई है, हो सकता है कि उसका कार्य कुछ ढीला रहा हो. उसमें यह संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। 1973 में उन अफसरों की संख्या, जिनको ट्रेनिंग मिली है, 8,875 थी और क्लर्क्स की संख्या 14,986 थी, 1974 में अफसरों की संख्या बढ़ कर 16,880 और क्लर्क्स की संख्या 22,814 हो गई और इस साल जो ट्रेनिंग कार्य चल रहा है यानी 1975 में अफसरों की संख्या बढ़ कर 21,704 होगी और क्लर्क्स की संख्या 34,499। इस प्रकार यह ट्रेनिंग बराबर बढ़ी है परन्तु जैसा कि हम लोगों का विचार है और हम दृढ़-प्रतिज्ञ हैं कि बैंकों के माध्यम से, आर्थिक ढांचे को ठीक किया जाए और उसकी गति बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा अंचलों तक इन सुविधाओं को ले जाया जाए, तो आज इस गति को बढ़ाना होगा और ऐसा करने के लिए कार्य-क्षमता, शैली और सभी चीजों का नवीनीकरण करना पड़ेगा। इसीलिए यह बिल आज आप के सामने आया है। माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि इसमें विलम्ब हुआ है और ऐसे महत्वपूर्ण बिल को पहले आना चाहिए था, यह सही बात है लेकिन मान्यवर यह विलम्ब हमारी ओर से नहीं हुआ है और इसके जो कारण है वे आप में से बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है और आप को भी मालूम है। सरकार की ओर से यह बिल पिछले साल नवम्बर में सदन के सामने आ गया था और काफी एमेंडमेंट्स भी आ गये थे पर सदन में उस वक्त इस पर विचार नहीं हुआ और उसके कारण भी स्पष्ट हैं। आज इस पर चार घंटे का समय लगा है। उस वक्त भी अगर यह महत्वपूर्ण बिल सदन के सामने विचार के लिए आता तो माननीय सदस्य अपने विचार देते। कहना यह है कि अब जब यह निश्चय हुआ है कि इस तरह का कमीशन स्थापित किया जाए, तो कमीशन स्थापित करते वक्त माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं, मैं उनको आश्वासन देती हूं कि उनके हरेक सुझाव पर अच्छी तरह से विचार किया जाएगा और सरकार चाहती है कि माननीय सदस्यों ने जो विचार

रखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उस कमीशन की स्थापना होगी, परन्तु मौलिक रूप से मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो दो चार चीजें हैं वे यह है कि यू० पी० एस० सी० के मौडल पर यह बिल बना है और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन्स के अनुसार इसको बनाया गया है ।

उम्र के बारे में जो जिक्र किया गया है और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो बातें कही गई हैं, ये सारी ही चीज यू० पी० एस० सी० के जो नियम है उन्हीं के आधार पर होंगी । मौलिक रूप से उसी आधार पर यह चीज बनी है । यह जो कहा गया है कि कमीशन में एक सदस्य शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का हो और उसके बारे में जो विचार रखे गये है उसके बारे में मैं अवश्य यह कहना चाहूंगी कि बिल में इस वक्त कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो इस चीज को रूल आउट कर दे कि वह नहीं आ सकते । बिल में ऐसी कोई स्पेसीफिक बात नहीं की गई है परन्तु यह भी जरूर है कि इसके लिए कोई रोक भी नहीं है । जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं और जैसे यू० पी० एस० सी० का कार्य चल रहा है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह सब किया जाएगा ।

हमारे बसुमतारी जी ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया और उस से मैं सहमत हूं कि जिस तेजी से राष्ट्रीयकृत बैंकों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आना चाहिए था, वह नहीं हुआ । मैं इस को स्वीकार करती हूं, इसलिए नहीं कि सरकार की ओर से मैं ऐसा कहती हूं बल्कि एक मां की हैसियत से यह बात कहती हूं कि उन की जो दिक्कत है उस को दूर किया जाए । उन के दिल पर जो चोट है, वह मैं जानती हूं और मैं उन को आश्वासन देना चाहती हूं, मैं यह तो नहीं कह सकती कि इतने समय के अन्दर यह चीज हो जाएगी पर यह जरूर है कि इस काम में तेजी लाएंगे । उन्होंने कहा कि एक फर्स्ट क्लास शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का है और सब तरह से क्वालीफाइड है लेकिन फिर भी उस को आज तक नहीं रखा है । मैं यह जरूर चाहूंगी कि यह चीज देखी जाए ।

सभापति महोदय : उन का कहना यह है कि क्या आप कुछ गाइडलाइन्स ले डाउन करेंगी कि आगे चल कर यह जो कमीशन बनेगा और वह जो रिक्रूटमैंट करेगा, उस में कोई परसेन्टेज उन की लेंगे ? ऐसी कोई गाइडलाइंस आप उन को देंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह सारी चीज उसी मोडल पर है जैसा कि यू०पी०एस०सी० में होता है लेकिन इस में कोई रूलआउट करने वाली बात नहीं है ।

सभापति महोदय : यह तो निगेटिव बात हो गई । कोई पाजीटिव बात आप करेंगीं और कोई आश्वासन देंगी, जिस से उन को तसल्ली हो जाए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह एश्योरेंस दे रही हूं पाजिटिवली कि माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी उस कमीशन पर हो, उस पर विचार किया जाएगा । जो कमीशन बनेगा, वह यू०पी०एस०सी० के मोडल पर होगा ।

नियुक्तियों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा और कुछ लोगों के मन में यह आशंका है कि नई नियुक्तियां करने से क्लास 3 और 4 क्लास के लोगों का प्रोमोशन रुक जाएगा । यह चीज नहीं है । इस में केवल यह चीज है कि अभी जो सारा प्रमोशन बेसिस पर हो रहा है, उस में से फिलहाल 25 प्रतिशत जगहों पर ही नये नये लोगों को इनडक्ट किया जाएगा ताकि नया फ्रेश ब्लड भी आ सके जिस से

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

आज कल जो आकांक्षाएं हैं, आज कल जो विचार हैं और आज कल की सामायिक चीजें हैं, वे पूरी हो सकें ।

सभापति महोदय : आप को याद होगा कि बहुत से एड-हाक एपाइन्टमेंट्स हो जाते हैं जिन को बाद में रेगुलेराइज कर दिया जाता है । तो इस कमीशन के आने के बाद ऐसा कोई प्रावधान किया गया है कि इस तरह की जो कुछ दिक्कतें हैं, वे दूर हों ? उनका भी कोई इन्तजाम आप इस में करेंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : एड-हाक के लिए प्रोविजन है ।

सभापति महोदय : पहले एड-हाक एपाइन्टमेंट्स हो जाते है और बाद मे उन को रेगुलेराइज किया जाता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह जो सारा काम है, जो रेगुलेशन्स बनेंगे, उन के अनुसार होगा और सारे प्रोविजन्स बिल में है । इस के अतिरिक्त मै यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो रेगुलेशन्स बनेंगे, वे गवर्नमेंट की एप्रूवल से बनेंगे ।

श्री पन्नालाल बारुपाल (गंगानगर) : मैं माननीय मंत्री जी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं हालांकि यह विषयान्तर होगा । हमारी प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है और उस से यह लिखा है कि कर्जों की माफ़ी होगी, भूमि मजदूर, छोटे किसान और दस्तकारो के कर्जों को वसूलने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्जे भी माफ़ होंगे या बनियों के कर्जे ही माफ़ होंगे ।

सभापति महोदय : यह सवाल कहां पैदा होता है । यह सवाल आउट आफ़ आर्डर है और इस का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The Commission is to make recomendation for appointment in the banks. The Commission will be the only source for selection of candidates for appointment in the banks.

यह जो आप ने प्रश्न किया, इन सब चीजों मे परिवर्तन करने का प्रयास हो रहा है और लोगों की राय से जितनी जल्दी जल्दी ये चीजे हो सकेंगी, उन को किया जाएगा ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूगी कि आज जो कृषि क्षेत्र मे विकास करने के लिए, एक नया कनसेप्ट बना है और जिस पर वित्त मंत्री जी भी बोले है, यह जो सर्विस सोसाइटीज का नया कनसेप्ट है, केवल धन से वहां पर विकास नही हो सकेगा । इसलिये धन के साथ साथ वहां पर ऐसे आदमियो की नियुक्ति हो जो वहा पर जा कर इन्तजाम कर सकें और लोगों को साथ-साथ अपना कन्सलटेशन भी दे सके । इस तरह से सारी चीजो का सामंजस करने की बात है ।

मेरे ख्याल से इस के बाद कितनी चीजें और कही गई है जैसे कि स्टेगनेशन का प्वाइन्ट था प्रोमोशन अपोरचूनिटीज की जो बात थी या शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो बातें उठाई गई थीं, उन पर भी विचार किया जाएगा । एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आनन्दमार्गियों के बारे मे भी उठाया गया है । मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस में कोई भी, कभी भी और कहीं का केस चाहे क्यों न हो, अगर किसी आदमी का ग़लत चीज से किसी प्रकार का सम्बन्ध है, उस के टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, पर मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्य ने इस चीज को उठाया

है, वह हमें स्पेसीफिक इन्सटांस, कोई भी हो, बगैर विलम्ब के पूरे प्रूफ के साथ दें ताकि हम कोई एकशन ले सकें। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे बीच में इस प्रकार की अगर कोई चीज है, तो उस को हम फौरन वहां से हटायें।

मेरा विश्वास है कि इस व्यवस्था से एक अच्छी परम्परा बनेगी, एक स्वस्थ कन्वेन्शन बनेगा, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सार्थक हो सकेगा। मेरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसको अपना समर्थन देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री स्टीफ़न ने बहुत ज़ोरों की धमकी दी थी। उस के बारे मे मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : स्टीफ़न साहब ने कुछ बात कही और उस का जवाब मेरे मित्र, श्री बनर्जी, ने दिया। माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार प्रकट किये हैं। दोनों दृष्टिकोण सामने आ गये हैं। मुझे इस के बारे में कुछ नही कहना है।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a Commission for the selection of personnel for appointment to services and posts in certain banking institutions and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

*Clause 2—(*Definitions*)

MR. CHAIRMAN: We now take up Clause by clause consideration. There are amendments to Clause 2; amendments Numbers 3 and 4.

Amendments made:

Page 2, line 15,—

for "constituted under" *substitute* "as defined in" (3)

Page 2,

after line 16, *insert*—

'(i) "regulation" means regulation made under this Act;' (4)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4—(*Appointment and terms of office of Chairman and members*)

MR. CHAIRMAN: There are amendments Nos. 5, 6 and 7 to Clause 4.

Amendments made:

Page 2, line 41,—

for "or any other matter" *substitute* "or in any other matters' (5)

Page 2, line 45,—

for "experience of" *substitute*—"such experience for" (6)

Page 3, line 3,—

after "this section" *insert*—"and of section 5" (7)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

*In view of Amendment No. 4 to Clause 2 adopted by the House, in clause 2, on page 2, in line 17, "(i)" was substituted by "(j)" and in line 19, "(j)" was substituted as "(k)" as patent errors under the direction of the Speaker.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 *Removal and Suspension of Chairman or the members from office in certain circumstances)*

MR. CHAIRMAN: We go to Clause 6. There is amendment by the Minister, No. 8. When you make the Bill, there seems to be more amendments than the Bill itself.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The Bill was introduced last year and now we are discussing it.

MR. CHAIRMAN: From last year you had time to think!

Amendment made:

Page 4, line 13,—

after "functioning as" *insert*— "the Chairman or" (8)

[Shrimati Sushila Rohatgi]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I think there are no amendments to clause 7. I shall put it to the vote.

The question is:

"That Clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

***Clause 10-** *(Competitive examinations for appointment in public sector banks)*

MR. CHAIRMAN: There is one amendment to this clause.

Amendment made:

Page 5,—

for lines 19 to 24, *substitute*—

"Duty of Commission to hold competitive examinations for appointment to posts in public sector banks.

10. (1) It shall be the duty of the Commission to conduct examinations for appointments in each public sector bank to—

(a) posts in the clerical and allied cadres and the Junior officers' cadre, and

(b) such other posts of, or posts in the cadres of, officers as the Central Government may, by notification, specify." (9).

[Shrimati Sushila Rohatgi]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clause 11 was added to the Bill.

---

*In view of Amendment No. 9 to Clause 10 adopted by the House, for the words "Competitive examinations for appointment in public sector banks" occurring in the marginal heading to clause 10, the words "Duty of Commission to hold competitive examinations for appointment to posts in public sector banks" were substituted as patent errors under the direction of the Speaker.

Clause 12—(*Duty of public sector banks to communicate to the Commission the number of vacancies*)

MR. CHAIRMAN: There are amendments to clause 12.

Amendment made:

Page 5,—

for lines 34 to 44, *substitute*—

"Duty of public sector banks to communicate to the Commission of number of vacancies.

12 (1) It shall be the duty of very public sector bank to communicate to the Commission—

(a) all the vacancies in the clerical and allied cadres or in such other post or cadre as may be specified by the Central Government under section 10, and

(b) twenty-five per cent of the estimated total number of vacancies in the junior officers' cadre,

which are likely to occur during the unexpired portion of the calendar year in which this Act comes into force and thereafter, as soon as may be, after the commencement of each calendar year:

Provided that, in relation to the junior officers' cadre, the Central Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do in the interests of the public sector banks, by notification, raise the percentage of vacancies to be communicated to the Commission to thirty-three and one-third per cent.". (10)

Page, 6,—

Omit lines 1 to 4 (11)

Page 6,—

after line 10, *insert*—

'Explanation.—In this Act, the expression "vacancy" includes a newly created post which has not been filled in'. (12)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clause 13. I shall put it to vote.

The question is:

"That Clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was addded to the Bill.

Clause 15— (*Communicated vacancies to be filled only on the recommendation of the Commission*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to this Clause.

Amendment made:

Page 6, line 43,—

for "communicated" *substitute*—

"required to be communicated" (13).

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 15, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

---

*In view of Amendment No 10 to clause 12 adopted by the House, for the words "the number of vacancies" occurring in the marginal heading to clause 12, the words "of number of vacancies" were substituted as patent errors under direction of the Speaker.

Clause 16- (*Power of Central Government to entrust other advisory functions to the Commission*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to Clause 16.

Amendment made:

Page 7, line 8,

omit "other" (14)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clause 17 to 28. I shall put them to the vote.

The question is:

"That Clauses 17 to 28 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 17 to 28 were added to the Bill.

Clause 29— (*Amendment of Act 14 of 1947*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to Clause 29.

Amendment made:

Page 9, line 25,—

for "1974" *substitute* "1975" (15)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 29, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to Clause 30 to 33. I shall put them to the vote.

The question is:

"That Clauses 30 to 33 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 30 to 33 were added to the Bill.

Clause 1—(*Short title and commencement*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to clause 1.

Amendment made:

Page 1, line 6,—

for "1974" *substitute* "1975" (2)

(*Shrimati Sushila Rohatagi*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: There is amendment to the Enacting Formula.

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Twenty-fifth" *substitute* "Twenty-sixth" (1)

(*Shrimati Sushila Rohatgi*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The title was added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, with your permission, I beg to move:

"That the Bill, as amended be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended be passed."

The motion was adopted.